श्री उपसभापति: जरा सुनिए।

श्री मूल चन्द मीणा: सर, नोटिस दिया है, तभी तो चर्चा हुई है और ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: नोटिस नहीं दिया गया है, आप सीनियर मैम्बर हैं, प्लीज... प्लीज... ...(**व्यवधान**)... Mr. Narayanasamy, I again want to remind you, ...*(Interruptions)*... Please respect the Chair. ...*(Interruptions)*... You must respect the Chair. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*... यह सही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री मूल चन्द मीणा: बात सुनिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मीणा जी, आप बैठिए... मैं बोलता हूं आप बैठिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: It should be referred to the Ethics Committee. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your demand to refer the matter to the Ethics Committee can be taken up by the Chairman. ...*(Interruptions)*... You give a notice. ...*(Interruptions)*... You give a notice. ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Okay, Sir.

DISCUSSION ON STATEMENT BY PRIME MINISTER--

India's Vote in I.A.E.A. on Iran's Nuclear Programme

श्रीमती सुषमा स्वराज (उत्तरांचल): उपसभापति जी, मुझे खुशी है कि इतने उतार-चढ़ाव और इतनी बाधाओं के बाद अंतत: इस विषय पर हम लोग सदन में चर्चा कर हैं। उपसभापति जी, हम इस सदन में उस वक्तव्य पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो वक्तव्य प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA गवर्नर्स बोर्ड की बैठक में ईरान के विरुद्ध भारत द्वारा किए गए मतदान के संदर्भ में 17 फरवरी का हमारे समक्ष दिया था। उपसभापति जी, IAEA में वोट के बाद, इस देश में कई तरह के विवाद खड़े हुए थे और हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री का यह वक्तव्य उन विवादों को शांत करेगा। यह हमारी जिज्ञासाओं का समाधान भी करेगा और देश में प्रकट की जा रही आशंकाओं का निराकरण भी करेगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि इसके ठीक उल्टा हुआ। जो वक्तव्य आया, वह इतनी दुविधा से भरा हुआ था कि सरकार तो दुविधा में है ही और उसने इस वक्तव्य के माध्यम से सदन को भी दुविधा में डाल दिया और सदन के माध्यम से देश को भी दुविधा में डाल दिया। इस वक्तव्य का कोई ओर-छोर नहीं है। यह वक्तव्य इतना लम्बा-चौड़ा है कि आप पढ़ने के बाद यह नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार यह सरकार क्या चाहती है। कभी इस वक्तव्य में ईरान प्रेम झलकता है, कभी इसमें अमेरिका प्रेम झलकता है, यदि इसमें कुछ नदारद है तो भारत प्रेम नदारद है। भारत-अमेरिका प्रेम और ईरान प्रेम

के बीच में झूलता हुआ नजर आ रहा है और यह दुविधाग्रस्त होकर खड़ा है। उनके वक्तव्य की प्रति मेरे पास है। पहले पैराग्राफ के पहले वाक्य में यह है कि 'सबसे पहले, मैं दृढ़तापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्ताव पर भारत के मत से ईरान के साथ हमारे परम्परागत, घनिष्ठता और मैत्रीपूर्ण संबंधों में किसी भी तरह कमी नहीं आएगी।' उपसभापति जी, चाहे जितनी दृढ़ता से प्रधानमंत्री जी ने यह बात हमारे सामने कही हो, लेकिन मोटी समझ, जिसे कॉमन सेंस कहते हैं, वह यह पूछती है कि क्या ऐसा हो सकेगा? यहां पूर्व विदेश मंत्री बैठे हैं और कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी बैठे हैं? मैं उनसे पूछना चाहती हूं, Do you genuinely believe that this would happen? उपसभापति जी, कूटनीति वन-वे ट्रेफिक नहीं होती। The very basis of diplomacy is reciprocity and mutuality. एक doctraine हमने जरूर सुना था, Gugral doctraine कि पाकिस्तान चाहे जो करे, लेकिन हमारे सद्भाव में कमी नहीं आएगी। अब यह जो दूसरा Doctor's Doctraine आया है, जहां कहा जा रहा है कि हम जो भी करें, ईरान के साथ संबंधों में कोई कमी नहीं आएगी। This is not only impossible; this is simply illogical. उपसभापति जी, प्रधानमंत्री जी अगले पैराग्राफ में कहते हैं "Let me reiterate in this context that we are committed to the proposed Iran-Pakistan-India gas pipeline. The economics of this project is currently under professional investigation by internationally reputed consultants. This is a necessary step in taking the pipeline project forward." अगर आज प्रधानमंत्री जी यहां बैठे होते तो मैं सात महीने पहले उन्हीं का दिया हुआ बयान, पढ़कर सुनाती। यह 20 जुलाई, 2005 का बयान है, प्राइम मिनिस्टर ने वाशिंगटन पोस्ट को एक इन्टरव्यू दिया। उसमें ईरान गैस पाईप लाइन के बारे में जो उन्होंने कहा है, मैं सदन को पढ़कर सुनाती हूं,। "I am realistic enough to realise that there are many risks, because considering all the uncertainties of the situation there in Iran, I don't know if any international consortium of bankers would probably underwrite this." यह सात महीने पहले का बयान है, जब स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी थी और ये दोनों वोट नहीं हुए थे। उस समय प्रधानमंत्री जी व्यवहारिकता के धरातल पर खड़े होकर वाशिंगटन पोस्ट का कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है जिस तरह के हालात बन रहे हैं उनमें कोई भी बैंकर उसके लिए पैसा देगा। और आज सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में यह कह रहे हैं कि पाइपलाइन आई कि आई। इस वक्तव्य में वे यह दिवास्वप्न क्यों दिखा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता।

उपसभापति जी, इस वक्तव्य के ये दो अव्यावहारिक पहलू बताने के बाद, अब मैं असली विषय पर आती हूं, जिसके बारे में यह वक्तव्य दिया गया है और उस विषय पर बात करते हुए, मैं सबसे पहले स्पष्टता से एक बात यहां कह देना चाहती हूं कि हम यह कतई नहीं चाहते कि

ईरान, परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ईरान, न्यूक्लियर वैपन स्टेट नहीं बनना चाहिए। हम यह कहते हैं कि ईरान NPT का हस्ताक्षरकर्ता है, वह हस्ताक्षरकर्ता बना रहना चाहिए। हम यह कहते हैं कि वह IAEA के कंट्रोल में है, वह IAEA के नियंत्रण में रहना चाहिए, लेकिन यह कह देने के बाद मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या इस लक्ष्य की पूर्ति हम उस अमेरिका के साथ खड़े होकर करेंगे जो ईरान को उकसा कर NPT से बाहर ढकेलना चाहता है, उस देश के साथ खड़े होकर करेंगे, जो ईरान के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, ईराक जैसे fake WMDs के बहाने ढूंढ रहा है।

उपसभापति जी, हम यह न भूलें कि ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध नहीं हैं, हमारे व्यापारिक हित भी उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश का 85 फीसदी तेल खाड़ी के देशों से आता हैं, हम जानते हैं कि हमारा 90 फीसदी गैस का भंडार खाड़ी के देशों से आता है, और अगर कल को अमेरिका ने ईरान के खिलाफ कोई कार्यवाही कर दी, तो हमारी अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो जाएगी। इसलिए ईरान के संबंध में निर्णय लेते समय हम इस पहलू की अनदेखी नहीं कर सकते। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इस तरह के पहलुओं के बारे में प्रधानमंत्री ने सोचा था, सरकार ने सोचा था?

उपसभापति जी, चाहिए तो यह था कि जिन संबंधों की दुहाई हम दे रहे हैं, जिन संबंधों का जिक्र और उल्लेख हम इस वक्तव्य में बार-बार कर रहे हैं, उन संबंधों का हवाला देकर हम ईरान को सही परामर्श देते, उससे वार्ता करते और अमेरिका जो गरमी फैलाने की कोशिश कर रहा है, उस गरमी को शांत करते। यह काम हमने किया था। हम आज IAEA के सदस्य नहीं बने हैं, भारत IAEA का स्थाई सदस्य है, बल्कि संस्थापक सदस्य है। इसलिए हमें मालूम था कि क्या हो रहा है। हमारे समय में हमने ईरान को engaged रखा। हमारे उस समय के विदेश मंत्री दो-दो, तीन-तीन बार ईरान गए। हमारे समय में हमने वोट की नौबत नहीं आने दी। हमारी कूटनीतिक सफलता इसमें होती कि ईरान के विरुद्ध वोट देने की नौबत न आती, लेकिन यह हमारी कूटनीतिक असफलता है। उपसभापति जी, यह हमारी कूटनीतिक असफलता है कि वहां ऐसे हालात पैदा हुए कि वोट देने की नौबत आई। अब मैं सरकार के तर्क पर आती हूं। सरकार का अगर यह कहना है कि नहीं, हमने सब कुछ करके देख लिया था, हमने बात भी की ली थी, परामर्श भी कर लिया था, लेकिन वह मानता ही नहीं था, वह बज़िद था NPT के violation, करने में, वह उल्लंघन किए जा रहा था और स्थिति ऐसी निर्मित हो गई थी कि हम क्या करते, इसलिए हमारे पास वोट देने के अलावा कोई चारा नहीं था, आपका यही तर्क है न? अगर आपका यही तर्क है, तो मैं आपसे दो सवाल और पूछना चाहती हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि अगर ईरान NPT का उल्लंघन कर रहा है, तो ईरान से NPT का उल्लंघन कौन करवा रहा है? आप जानते हैं कि यह काम और कोई नहीं करवा रहा है, यह काम पाकिस्तान करवा रहा है। आप यह

बात जानते हैं न? यह काम और कोई नहीं करवा रहा है यह centrifuges देने का काम पाकिस्तान करवा रहा है। तो आपने यह क्यों नहीं कहा कि NPT का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ अगर कार्यवाही होनी चाहिए, तो उल्लंघन करवाने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए, यह बात मैं नहीं कह रही हूं, यह बात IAEA की reports में कही गई थी और IAEA की reports में बेवजह नहीं कही गई, अंदाज़ों के आधार पर नहीं कही गई, अटकलों के आधार पर नहीं कही गई, उन दोनों के बयानों के आधार पर कही गई है, जिन्होंने लिया है और जिन्होंने दिया है। ईरान लेने वाला है। उसने कहा कि मुझे ये सेंट्रिफयूजेज पाकिस्तान ने दिए हैं। पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने कहा है कि हमारे परमाणु कार्यक्रम के मुखिया ए.क्यू. खान ने ये सेंट्रिफयूजेज ईरान को दिया है, यह टेक्नोलॉजी ईरान को ट्रांसफर की है। जिस रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रही हूं, उस रिपोर्ट को मैं पढ़ कर सुनाना चाहती हूं। यह डीजी, आईएईए की रिपोर्ट है, ऊपर लिखा है—"Please note: References in the report to P1 and P2 stand for Pakistan1 and Pakistan2. Centrifuge designs for uranium enrichment provided to Iran by the procurement network led by A.Q. Khan in Pakistan." डीजी, आईएईए की रिपोर्ट में नाम लेकर कहा गया है कि ये सेंट्रिफयूजेज पाकिस्तान ने ईरान को दिए। मेरा आपसे सवाल है कि आपने यह प्रश्न वहां वोट देने से पहले क्यों नहीं उठाया कि अगर एनपीटी का उल्लंघन करने वाले ईरान के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो एनपीटी का उल्लंघन करवाने वाले, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? आपने यह प्रश्न इसलिए नहीं उठाया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि आप पाकिस्तान का नाम लें। अमेरिका, ने तो आपको इनलाइटेन कर दिया है। ये नए फेजेज आए हैं, कहां से नई डिक्शनरी आई है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम यह काम इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट के अन्तर्गत कर रहे हैं और पाकिस्तान कह रहा है कि हम यह इनलाइटेंड मॉडरेशन के अन्तर्गत कर रहे हैं, यह मुशर्रफ कर रहे हैं। ये दोनों मुखिया बोल रहे हैं। यह कौन-सा बोधि-वृक्ष है, जहां से इनलाइटेनमेंट आता है? उपसभापति जी, एक बोधि-वृक्ष का नाम तो सुना था, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ था, लेकिन यह अमेरिकन वृक्ष बोधि-वृक्ष से भी बड़ा हो गया कि दो-दो पड़ोसी देश, जो एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ते भी रहे, आज भी जहां सीमा पार आतंकवाद चल रहा है, वे दोनों के दोनों देश एक ही भाषा बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने इनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट के अंतर्गत किया और मुशर्रफ कहते हैं कि हम इनलाइटेंड मॉडरेशन कर रहे हैं।

मुझे इससे भी ज्यादा बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान का नाम आपने वहां तो नहीं लिया, लेकिन वह नाम आप यहां भी लेते हुए घबरा रहे हैं। यह वक्तव्य है प्रधानमंत्री का। क्या कहते हैं? "Hon. Members are aware that the source of such clandestine proliferation of scientific technologies lies in our own neighbourhood,

details of which have emerged from successive IAEA reports. Neighbourhood! नेबरहुड तो हमारा बहुत लम्बा-चौड़ा है! कितने पड़ोसी देश हैं हमारे? बंगलादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, मालद्वीव है। क्या इनमें से किसी एक का नाम आईएईए की रिपोर्ट्स में आया है? आपने कहा है कि सक्सेसिव आईएईए की रिपोर्ट्स में नाम आए। मैं पूछना चाहती हूं, बताइए कि क्या किसी एक का नाम आया है आईएईए की रिपोर्ट्स में, सिवाय पाकिस्तान के? अगर नहीं आया, तो आप यहां नेबरहुड क्यों कह रहे हैं? कम-से-कम अपनी संसद के सामने बोलते हुए, अपने सदन के सामने बोलते हुए तो सच बोलिए, उनके सामने तो फैक्ट रख दीजिए, उनके सामने तो तथ्य रख दीजिए। लेकिन आप नहीं कहेंगे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि आप उनका नाम लें। आईएईए की रिपोर्ट्स के बारे में क्या, दिल्ली में जब बम-ब्लास्ट हुए, बम-विस्फोट हुए, उसमें रिपोर्ट आ गई कि आईएसआई के कहने पर लश्कर-ए-तैय्यबा ने बम-विस्फोट कराए। आपने वहां भी नाम नहीं लिया। आपने क्या कहा-"There is an external link to these incidents." External link!

मैं पूछना चाहती हूं कि आप अमेरिका के सम्मोहन से इतने क्यों बंधे हैं? उनका राजदूत आता है, आपको धमकी देता है और आप मौन रहते हैं। सारे कूटनीतिक आचारों को धता बता कर वह राजदूत एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिटठी लिखता है और आप मौन रहते हैं। उपसभापति जी, मैं कहना चाहती हूं कि यह केवल उस राजदूत की हेकड़ी का प्रदर्शन नहीं है, यह हमारी विदेश नीति की कमजोरी का भी प्रदर्शन है कि एक राजदूत आकर कहे कि अगर आप ईरान के खिलाफ वोट अमेरिका के साथ नहीं करेंगे, तो आपका परमाणु समझौता रद्द कर दिया जाएगा। एक राजदूत प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह कहे कि अगर आप सीधे नहीं होंगे, अगर आप अपनी नीति नहीं बदलेंगे, तो अमेरिका का सारा पूंजी-निवेश पश्चिम बंगाल से निकाल दिया जाएगा। इस सारे के बाद वह राजदूत दनदनाता रहे और आप यह कहते रहें कि हमने अमेरिका के दबाव में वोट नहीं दिया। कौन मानेगा आप की बात? कौन सुनेगा आप की बात? अगर आप वाकयी सच्चे थे कि आप अमेरिका के दबाव में वोट नहीं दे रहे थे तो ऐसे राजदूत का बोरिया-बिस्तरा बांधकर वापस भेज दिया होता और उस के बाद वोट देते तो लोग यह कहते कि आप ने अमेरिका के दबाव में वोट नहीं दिया।

उपसभापति जी, हमारा अमेरिका से कोई स्थायी विरोध नहीं है, वामपंथी साथियों की तरह कोई दुराग्रह भी नहीं है। हमारे संबंध भी अमेरिका से अच्छे रहे हैं। आज भी अच्छे हैं, लेकिन वे संबंध हमेशा राष्ट्र हित से प्रेरित संबंध रहे हैं। हम ने कभी अमेरिका का दबाव नहीं माना। मैं याद कराना चाहती हूं इस सदन को जब हम ने पोखरन-2 का फैसला किया था, हमें मालूम था कि अमेरिका हमें आंखें दिखाएगा, हमें मालूम था हमारे खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। हम बच्चे नहीं थे। हमें यह बिल्कुल मालूम था कि उस की प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन राष्ट्र हित का तकाजा

था कि हम ने बिना दबाव में आए धड़ल्ले से पोखरन-2 का विस्फोट किया था और भारत को एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र बना दिया था। उस के बाद प्रतिबंध लगे थे, लेकिन प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए हम उन के सामने गिड़गिड़ाए नहीं थे। हम ने प्रतिबंधों का दृढ़ता और सफलता से सामना किया था और इतिहास गवाह है कि वही क्लिंटन प्रशासन जिस ने प्रतिबंध लगाए थे, वही अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए थे और उसी शासन के दौरान आए थे जिस शासन ने पोखरन-2 का विस्फोट करने का फैसला किया था। इसलिए मैं आप से कहना चाहती हूं कि आप क्यों भयभीत होते हैं, आप क्यों सकुचाते हैं? हमारी विदेश नीति न अमेरिका प्रेम से प्रेरित होनी चाहिए, न ईरान प्रेम से। वह केवल और केवल भारत प्रेम से प्रेरित होनी चाहिए, केवल और केवल राष्ट्र हित से प्रेरित होनी चाहिए।

आप एक और औचित्य देते हैं और कहते है कि, देखिए nuclear weapon देशों ने इस बार वोट किया। वह चीन और रूस जिन्होंने पहले वोट नहीं किया था, इस बार उन्होंने वोट दिया। उपसभापति जी, मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या आप को जानकारी नहीं है कि इन लोगों ने क्यों वोट दिया? क्या आप को यह जानकारी नहीं है कि पी-5+प्लस 1 जर्मनी-इन 6 देशों की लंदन में एक गोपनीय बैठक हुई थी और उस बैठक में सब ने अपने-अपने हित सुरक्षित किए थे। फ्रांस ने कहा था लेबनान छोड़ दो, चाइना ने कहा था हमारी इनर्जी सेक्युरिटी सुरक्षित कर दो और चाइनीज फर्म्स पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन को रिन्यू मत करो। रूस ने कहा था ईरान के यूरेनियम संवर्धन का काम हमारी धरती पर होने दो। ये हुआ था न? उस के बाद एजेंडा तैयार करके और यह प्रस्ताव लेकर वे आई०ए०ई०ए० के सामने आए थे और वहां भी ईजिप्ट जैसे छोटे देश ने अपना संशोधन स्वीकार करवा लिया कि मिडल ईस्ट का पूरा रीजन न्यूक्लिअर वेपन फ्री होगा। क्या वह समय नहीं था जिस समय हम अपनी बात मनवाते? वह समय था जब हम पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही की बात उठाते और अपने हित को सधवाते। उन्होंने वोट जरूर दिया, लेकिन सब ने अपने-अपने हित साधकर वोट दिया, लेकिन आप लोगों ने अपना हित साधने का काम नहीं किया और आप केवल ठप्पा लगाकर चले आए। उपसभापति जी, जब मैं बार-बार कहती हूं कि अगर अमेरिका कार्यवाही करे तो हिंदुस्तान का क्या होगा? लोग यह कह सकते हैं कि मैं यह बात लायी कहां से? मेरे दिमाग में यह भ्रम क्यों है? मेरे दिमान में यह भ्रम नहीं है। अमेरिका जैसे देश को जंग ही हुड़क होती है और यह हुड़क पूरी करने के लिए वह नकली भेड़िए दिखाने का आदी है। उस ने वे ईराक में दिखाए थे फेक डब्ल्यू०एम०डी०एस० के नकली भेड़िए और अब वह ईरान की नीयत का सवाल उठा रहा है। यह तो अमेरिका का भी कहना नहीं है कि ईरान के पास परमाणु बम है। प्रधान मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि, नहीं वह आई०ए०ई०ए० को सहयोग तो कर रहा है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर सहयोग नहीं कर रहा है। यह तो अमेरिका भी नहीं कह रहा है कि ईरान ने परमाणु बम बना रखा है, लेकिन कहते हैं नीयत में खोट

है। चलिए, मैं मान लेती हूं कि नीयत में खोट है। तो नीयत में खोट है, इसलिए आप कार्यवाही करेंगे और नीयत में खोट है, इसलिए आप कार्यवाही करेंगे, यह बात मैं नहीं कह रही हूं। यह बात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिफेंस कॉंडलीजा राइस ने कही है। मैं वह बयान आप को पढ़कर सुनाना चाहती हूं। "We plan to spend 85 million dollars for political change in Iran: Rice". यह बयान है, क्या कहा है कॉंडलीजा राइस ने और कहां कहा है। The Secretary of State, Condoleezza Rice, announcing a request for money at a Senate hearing on Wednesday, at a Senate hearing, बाहर कहीं नहीं बोलीं, at a Senate hearing. She said, "The Administration had worked out a way to circumvent American laws barring financial relations with Iran to allow money to go directly to groups promoting change inside the country."

नीयत में खोट किसकी है? अगर उनकी नीयत यह है, तो अगर कल कोई कार्रवाई होती है, तो जिस सुरक्षा का प्रश्न उठाकर हम वोट कर रहे हैं, क्या इससे सामरिक सुरक्षा के साथ-साथ हमारी आर्थिक सुरक्षा ध्वस्त नहीं हो जाएगी? इसीलिए मैं बार-बार कह रही हूं कि हमारी नीति हमारे हित से प्रेरित होनी चाहिए। अमेरिका का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह खाड़ी के देशों से 20 फीसदी तेल लेता है। वह कहीं और से ले लेगा, लेकिन अगर अर्थ-व्यवस्था किसी की चकनाचूर होगी, तो हमारी होगी। इसलिए उपसभापति जी, मैं कहना चाहती हूं कि कंडोलीजा राइस ने जो कहा है, हम इन चीजों की अनदेखी नहीं कर सकते। हम अमेरिका की नीयत की अनदेखी नहीं कर सकते। यह ठीक है कि ईरान की नीयत में खोट होगा, लेकिन क्या सामर्थ्य है, ईरान की? नीयत और सामर्थ्य में फर्क होता है सामर्थ्य अगर कोई जुटा सकता है, तो केवल पाकिस्तान जुटवा सकता है। अगर हम इस सामर्थ्य को ही समाप्त कर दें, तो ईरान परमाणु बम कैसे बनाएगा? यह एक रिंग है, स्मगलिंग रिंग और उस समय इस रिंग को तोड़ने का समय था। हम कह सकते थे, हम आज भी कह सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम न आज बोल रहे हैं, न हम वहां बोले और न हम सदन के सामने बोले। हम तो कतरा रहे हैं। हम तो संकोच कर रहे हैं । हम तो भय खा रहे हैं।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आज समय का तक़ाजा है कि हम अपने राष्ट्र-हित को सामने रखते हुए अपनी नीति में इस तरह का परिवर्तन करें कि हमारे रिश्ते न तो ईरान से बिगड़ें और हमारे क्षेत्र की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह भी न लगे। हमारा यह रिज़न आज विश्व का सबसे ज्यादा अनस्टेबल रिज़न है। हम एक ज्वालामुखी के दहाने पर बैठे हैं। यह न्यूक्लियर कार्ड और न्यूक्लियर वेपन दिखा कर के जो बात की जा रही है, वह तो नकली भेड़िया हो सकता है, लेकिन यह ज्वालामुखी, जिसके दहाने पर हम बैठे हैं, यह नकली नहीं है। एक चिंगारी अगर सुलग गई, तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इसी वक्तव्य के पृष्ठ 3 के अन्तिम पैराग्राफ में प्रधान मंत्री जी ने एक बात कही है—

"सभापति महोदय, हम सभी सम्बन्धितों से संयम बरतने, लचीलापन दिखाने और वार्ताएं जारी रखने का आग्रह करते हैं, ताकि इस समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकाला जा सके।"

मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार यह किससे कह रही है? सम्बन्धित कौन हैं? करना किसे है? हम तो विपक्ष में बैठे हैं, बोल-बाल के चुप हो जाएंगे। हमारे वामपंथी साथी बैठे हैं। आपके समर्थक दल हैं। अन्दर कोऑर्डिनेशन कमेटी में बात उठा लेंगे या सदन में बात उठा लेंगे। हम लोग बाहर जाकर प्रेस कांफ्रेस में अपनी बात कह देंगे, लेकिन हम कर तो नहीं सकते करने की भूमिका तो आपकी है। यह आग्रह आप किससे कर रहे हैं? संयम बरतने, लचीलापन दिखाने और वार्ताएं जारी रखने का आग्रह करते हैं। यह संयम आपको बरतना है, यह लचीलापन आपको दिखाना है, ये वार्ताएं आपको जारी रखनी हैं। इसलिए मैंने प्रारम्भ में कहा कि चाहिए तो यह था कि हम अपने डिप्लोमैटिक इनिशिएटिव से ये वार्ताएं जारी रख कर यह नौबत ही न आने देते।

अभी 6 मार्च को फिर वोट होना है, ज्यादा दिन नहीं हैं। फिर हमारी परीक्षा की घड़ी है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यह बात,जो आपने सभापति महोदय के माध्यम से हमसे कही है, यह बात आप करिए। आप संयम बरतिए, आप लचीलापन दिखाइए, आप वार्ताएं जारी रखिए और 6 मार्च को जब कोई परिस्थिति फिर निर्मित होती है, तो ऐसी परिस्थिति के निर्माण से बचिए, जैसी परिस्थिति दो बार पहले भी पैदा हो चुकी है। अगर इस परिस्थिति के निर्माण से आप बच सकें, तो उपसभापति महोदय, मैं मानूंगी कि आज की चर्चा सार्थक रही और यह इस चर्चा की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। धन्यवाद।

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Thank you, Mr. Deputy Chairman. क्योंकि आपने हिन्दी में बोला, तो मैं अंग्रेजी में बोलूं ...(व्यवधान)... इस तरह एक संतुलन भी रहेगा। ...(व्यवधान)... तेलुगू में बोलूं, अगर आपकी इजाजत हो, तो। ...(व्यवधान)... Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise here today to express my party's displeasure and sense of anguish over the manner in which India voted at the IAEA on the issue of Iran's nuclear programme. Because the issues are not confined only to the specific nature of the apprehensions that Iran is developing an atomic bomb or is developing nuclear weapons.

But these are issues which have a larger bearing on India's foreign policy and also a larger bearing on how India conducts itself in the international affairs in the world today. With this in mind, Sir, I think, this is a very important discussion that is taking place and I am glad that it's finally happened despite all the hiccups. I am also glad that the Deputy

Leader of the BJP has also taken special interest. I also thank you in the process in having this discussion conducted. But, Sir, we have heard the Prime Minister in this House talk in terms of enlightened nationalism; we have heard the Prime Minister talk in terms of how this nationalism evolved over a period of time after India became independent through the process of decolonisation. It is precisely from those tenets of this enlightened nationalism, Sir, my objections and my opposition to this vote comes. This enlightened nationalism emerged in the post-colonial world, in the process of decolonisation. So, India emerged as the leader of many of these colonial countries, we took the lead and even a year before we were independent, in 1946, we convened the Afro-Asian Conference, India emerged as a leader of the former colonies in terms of setting the agenda of what should be the contours of the world and what should be the contours of international development; and as a process of that enlightened nationalism, the conception of non-alignment arose. Non-alignment surely was not playing the ball between two walls and making best in the bargain. Non-alignment also had a very strong, I think, a principled position—I wouldn't call it ideological, but definitely, a principled position that India as a nation is not to be cowed down by any superpower in the world and we will take our position independently and play our natural role in the world. The natural role in the world for India would be as a leader of the developing countries in the world. It is this role which was the product of that enlightened nationalism, Sir, which I think today is actually being forsaken. That is why, I said, I speak with a sense of anguish. I speak with a sense of anguish because all that we laid out in front of the world, we laid out in terms of diplomacy, we laid out in terms of principles of international relations, the contributions that India has made all along in this more than half a century, have all today been put to test by this particular position that we have taken. That is why this sense of anguish is there. We appreciate, on this specific issue on Iran, that the Prime Minister in his statement has actually said, "It is our hope and belief that the issues that have arisen can still be resolved through discussion and dialogue." It is very correct. We are very happy that this hope is there. But where we are unhappy is that this does not rule out confrpntation and that is what ought to have been India's position— that these issues must be resolved only through dialogue and discussion, and not through confrontation. And why I am seeking this distinction regarding confrontation is that we believe that is precisely

the path that the USA is trying to tread today. It is this confrontational path that has to be avoided. And for that, Sir, what was our position before the first vote in IAEA took place? India had set out four points and these four points were contained in the Government's official documents. They said, India's first point was, India sought a negotiated settlement of the problem. The second point was, India acknowledged Iran's right to conduct a peaceful nuclear programme as a member country of the NPT. The third point was, India expected Iran to fulfil its commitments and obligations, as spelt out in these international agreements. And the fourth point was, India saw possibilities for resolving the problem within the framework of Iran's cooperation within the IAEA. So, very clearly, extending beyond the framework of IAEA has never been India's stated position and that is what we are doing right now and that is why, I think, this is a breach, a very serious breach, of our enlightened nationalism and our foreign policy when we are actually tyring to take this issue beyond IAEA and become a party to the United States and to the European Union sponsored move, to take this towards United Nations Security Council. And this is where we think that this enlightened nationalism, far from being carried forward, is actually being breached and, in that context, we urge upon this Government that it has to do a serious rethinking on this issue and ensure that on the 6th of March, we do not vote along with the United States of America. Why we should not vote, I will come to that later.

But, we must take our independent position and our time-tested position of abstaining on that vote on the 6th of March, which should be the position the Government should take, and this is what we urge them. Why do I say this? What are India's concerns? The Prime Minister in his statement has said: "Yes, we do not want any other nuclear weapon country in our region; we do not want Iran to acquire nuclear weapons. Very true, very correct. I wish there was a similar concern about Israel having more than 200 nuclear weapons today. There is not a word about it; there is not a word about this proliferation from where it is going. Shrimati Sushma Swaraj has raised this point. But how this proliferation took place from our neighbourhood, Pakistan? What are we suggesting about that? There is not a word about it. But, yes, okay, we do not want Iran to acquire nuclear weapons. But, Sir India's position has always been that we not only do not want Iran to acquire nuclear weapons, but we also do not

want nuclear weapons at all in any country in the world. What happened to the Rajiv Gandhi plan? This country had very proudly announced in the United Nations General Assembly that by the year 2010, the world should rid itself of all nuclear weapons. Rajiv Gandhi plan is dead and buried today. You have come to 2006. Nobody is talking in terms of elimination of nuclear weapons from this planet; nobody is talking of universal nuclear disarmament, and that is a serious departure from our enlightened nationalism, and that is the serious departure and breach of our enlightened nationalism, and that is something, which this Government must understand and correct.

Further, Sir, suppose, even for a moment, Iran is pleading that it has no nuclear weapons, but it is conducting a civilian nuclear programme. Suppose, for a moment, it is not saying the truth, and it is actually proceeding with a nuclear weaponization programme. What should be the position of India and how to stop that? Yes, we do not want them to have the nuclear weapons, like I said, we do not want anybody to have any nuclear weapons. But how do we stop them? What was enunciated by the Prime Minister himself earlier in the four points that I have read out, the only way is to ensure that Iran sticks to its obligations and duties in the Nuclear Non-Proliferation Treaty, and the Agency that can enforce that, which sticks to that, is the International Atomic Energy Agency. There is no scope for any other international body to enter into this dispute, and any effort that is made to treat this outside the IAEA is actually violating the international law, as it stands today, and it also violates, and I am sure, there are enough lawyers on International Law here, who will accept the fact that it violates an international principle called *Jus Cogens*. No international treaty can be violative of my country's internal legal situation, and this is violative of *Jus Cogens*, which is a treaty accepted by the International Law and the international community, and by referring Iran outside the IAEA to the United Nations Security Council, you are violating *Jus Cogens*, and India cannot be a party to such a violation because, it is violation of the International Law, and if India has to be a party to such a violation as well, why is it so, I will come to that later. But, instead of taking this course, when the Prime Minister himself said in his statement, and I quote: " Iran did extend cooperation to the IAEA." This is what he says. And what does the report of the Director-General of the IAEA tell you. I am quoting from the summary of that report. It says: "The Director-

General's report to the Board clearly stated that Iran was cooperating fully with the IAEA in terms of access and also information it had provided about its past programme have been confirmed by further investigations. The report also stated that some more time would be required to verify all claims and clarify all doubts." Sir, please go back 10 year ago, go back a few years ago, not even ten years ago. Mr. Hans Blix, the United Nations Inspector, who was operating in Iraq, he came back and reported to the Security Council saying the same sentence, some more time would be required to verify all claims and clarify all doubts. That time was not provided. The air strikes took place, the sanctions were imposed, finally, the aggression and finally the occupation. What is being done with Iran today is exactly what was done with Iraq 10 years ago. That is the blue print that is unfolding and the world is pushed on to that road map. Sir, when all this controversy is going on, please bear with me for a minute, I want to quote the former IAEA Deputy Director-General for Safeguards, Mr. Bruno Pellaud.

He had said, "Iran took a major gamble in December, 2003 by allowing a much more intrusive capability to the IAEA. If Iran had had a military programme, they would not have allowed the IAEA to come under this Additional Protocol. They did not have to". But yet Iran did. We ourselves admit, our Prime Minister himself admits, that in that situation we can't be a party to pushing Iran on to the road of Iraq and its final occupation as had happened ten years ago. I am afraid, India is actually subscribing to that particular agenda and that is where my anguish comes from. We can't, India can't lend itself to such a strategy that American interests dictate globally and that is what we have to oppose.

Now, if that is the case, what should be our stand? We have often been told, "We have taken this stand because five permanent members of the United Nations have taken this stand. How can we be isolated from them?". When we said, "You take the stand of NAM", we were told, "The NAM is divided in three ways. You had six countries for the motion, five countries abstaining and three countries against the motion. Since the NAM was divided, we decided to take our independent position". But India's greatness and India's claim to a certain distinctiveness in international politics lies in the novel suggestions that it had made in international disputes over the last fifty years. At every time we made a novel suggestion and there was a novel suggestion for us to make this

time also. But the Government has missed the bus. The dispute in Iran is on the question of nuclear uranium enrichment. India had an option and it could have taken a much more imaginative position which would have addressed both sets of issues, Iran's sovereignty and the right to peaceful uses of nuclear energy. What was this option? This option was a joint nuclear facility with multinational staff to actually supervise the uranium enrichment that is taking place in Iran. Today, the dispute is that it will be done by Russia on Russian soil. Iran says, "No, we will do it on our soil". Why didn't India take up this sort of an initiative or some sort of an alternative proposal to the world body? If the world body has rejected it, that is a different matter. But India's distinctiveness lies in that and it is that distinctiveness, I am afraid, we really abdicated in this particular situation.

My concern for this comes also from the global background. Why is it that we have expressed our concerns a number of times? There are three elements of the US global strategy which India must know. One element has been pre-emptive strikes or what it calls it has a right to strike at any country if the US perceives that it is not pursuing policies that suit the American interests. The second one is the entire question of regime change. We have just heard Shrimati Sushma Swaraj pointing out how 85 million dollars were sought for regime change policies? The third and the major one is essentially the US hegemony that is taking place in order to control the entire world. Now, in this situation, I can only quote what Mr. Harold Pinter, who won the 2005 Nobel Prize for literature, one of the well-respected persons of literature and art and intellect in the world. This is his acceptance speech of the Nobel Prize. I must congratulate him for his courage in actually saying this. He says-

* Its officially declared policy is now defined as 'full spectrum dominance'. That is not my term, it is theirs. 'Full spectrum dominance' means control of land, sea, air and space and all attendant resources.

* The United States now occupies 702 military installations throughout the world in 132 countries...

* The United States possesses 8,000 active and operational nuclear warheads. Two thousand are on hair trigger alert, ready to be launched with 15 minutes warning.

Now, if this is the global scenario that is developing, what should be India's position? What does the report filed on 12th February, 2006 in London's **Sunday Telegraph** say?

What does it say? It says, "Strategists at the Pentagon are drawing up plans for devastating bombing raids backed by submarine-launched ballistic missile attacts against Iran's nuclear sites as a 'last resort to block Teheran's efforts to develop an atomic bomb." A senior Pentagon adviser said, "This is more than just the standard military contingency assessment. This has taken on much greater urgency in recent months." The USA is preparing to strike Iran. It is preparing to strike Iran like it has struck Iraq 10 years ago through military strikes. It is preparing to use its ally, Israel in this region in order to help its occupation of Iran following what it did in Iraq. All this is happening not only in terms of global military hegemonism but also political hegemonism. This is where we all have to come to this....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How much time do you require?

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, five minutes more. This is where we all have to come to this clarity that why is all this happening, whether it is the occupation of Iraq; whether it is the targeting of Venezuela which is the world's second largest oil exporter; whether it is the targeting of Iran. All this is for control of the world's energy resources and it is this control of the world's energy resources that will affect us immediately and very acutely. If today war breaks out and the occupation of Iran happens, your oil prices internationally will zoom and pressure will be on you to increase the prices in the country. Each one of us will pay the price for the US occupation of Iran. We are paying the price for the US occupation of Iraq. We will pay the price for the US occupation and attack on Iran. Why are we subscribing to this strategy? That is the question. Why are we subscribing to this strategy? If the strategy is that in return you will get a better civil nuclear deal, then let me tell you the energy gains you will get through such a nuclear deal will be washed off by the international hike in oil prices and all that will be gone and you will end up as a loser. It is not even a pecuniary economic gain. In fact, nuclear deal is a different subject. The Prime Minister will make a statement and we will discuss that later. Even in terms of short-term economics, what the Prime Minister says is that India should be self-sufficient in its nuclear energy. But nuclear energy is only 3 per cent of our total energy production

today. However much you increase it, you will have to buy oil from abroad and if the price of that oil is raised because of this attack, then we are the ultimate losers. It does not even help us even from that narrow point of view. Having said this, when we put all this together we say that we should oppose this position for another reason. The International Atomic Energy Agency has identified 15 countries, which it suspects, are doing clandestine weaponisation and they include South Korea, Taiwan and Brazil. But why are you singling out Iran? Why is there no word against Israel? That is why it comes in; it fits into this geo-politics of the US strategy. Whenever we raise this, very interestingly, the question that comes is that: don't communalise the issue. It is not my fault that Iran is an Islamic country. It is not my fault that Iraq is an Islamic country. It is not my fault that even in Saudi Arabia most of the oil wells are there in the Shia dominated areas. If Americans start attacking and doing this in this way it is not we who are communalising the situation in the world, it is not those who oppose America who are communalising the situation in the world, it is the US itself and its actions that are communalising the situation in the world and they are the ones who are actually giving force to this communal wheel.

Here I would like to quote Harold Pinter again. Sir, I am sure, you will also enjoy this. He says that Bush, unfortunately, does not have good script writers. He says that if you want, I will volunteer to be the one. Since he has won the Nobel Prize in Literature, I am sure, they will consider it. Here is what he writes for Bush in his speech. It begins by saying, "God is good. God is great. God is good. My God is good. Ben Laden's God is bad. His is a bad God. Saddam's God was bad, except he did not have one. He was a barbarian. We are not barbarians. We don't chop off people's heads. We believe in freedom. So does God. I am not a barbarian. I am the democratically elected leader of a freedom-loving democracy. We are a compassionate society. My God is good. His God is bad" If one God is good and another God is bad, what else is this but communalisation?. I am sure my esteemed colleagues will agree with me. That is exactly the point.

Finally, Sir, I would like to say as to who is communalising this entire thing.

Actually, George Bush went on to the extent of saying that God came to him in the form of enlightenment. Mrs. Swaraj was talking about

the Bodh tree. But then, God made an enlightened appearance to him and said, "Attack Afghanistan; attack Iraq." Of course, he must have also said, "Attack Iran". And now, we are all led to believe that God came to him in a wave of enlightenment and said, "Attack these countries", and, therefore, he did it. What else is it but communalisation? Who is communalising it? Therefore, Sir, finally, I would like to say, on this, let us build a national consensus. Let us build a national consensus, because I am very glad; I have come prepared – the hon. Leader of the Opposition is here – with one of the articles about his speech on the Commonwealth Conference at California on 20th September, 2000. It says: "His Excellency, Shri Jaswant Singh, the Minister of External Affairs of India, said...." I won't labour on it, because the position that Swarajji has taken from that is clear. There, it says...

श्रीमती सुषमा स्वराज: जो बोला है, उस पर कायम रहो। ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: अरे, थोड़ा तो बोलना होगा। ...(व्यवधान)... अभी उस पर आ रहा हूं। ...(व्यवधान)... आप सुनिये। आप थोड़ा सब्र रखते, तो आप मेरी बात को और मानते। ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बात यही है कि यह जो नेशनल कंसेंसस जो इमर्ज हो रही है, हमें इस बात की खुशी है। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: आपको खुशी है, तो ...(व्यवधान)...

श्री सीताराम येचुरी: आप एक मिनट सुन लीजिए। एक वह भी जमाना था। ...(व्यवधान)... सुषमा जी, हम यह नहीं चाहते कि नेशनल कंसेंसस और एनलाइटेन्ड नेशनलिज्म इस पर निर्भर करे कि कौन सत्ता में है और कौन विपक्ष में है? अब यह न हो कि आप यहां पर रहो, तो अमेरिका के पक्ष में बात करो और वहां पर रहो तो इनलाइटेन्ड नेशनलिज्म की बात करो, यह नहीं होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि यह परिस्थिति न हो। हम विनम्रता से आप सभी से यही अपील कर रहे हैं कि अब हमारे देश के हित के लिए, हमारे देश की इज्जत के लिए आप कदम उठायें। आज की परिस्थिति में हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि जब 6 तारीख को वोट की नौबत आयेगी, अगर वोट की नौबत नहीं आये, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वोट की नौबत आये, तो आप तटस्थ रहियेगा, अमेरिका के साथ मत जाइयेगा। बुश साहब यहां आ रहे हैं, तो उनसे आप स्पष्ट रूप से कहियेगा, भाई "अतिथि देवो भव:", हम तो स्वागत करते हैं। ...(व्यवधान)... सर, प्लीज दो मिनट। "अतिथि देवो भव:" की आप बात करते हैं। आप याद रखियेगा, हमारे पुराणों की कहानियों में वामन के अवतार में विष्णु आते हैं, महाबली के चैम्बर में आते हैं, जैसे - आपके चैम्बर में हम आते हैं, जहां पर वह आये और महाबली कहते हैं कि जो भी वर चाहिए मांग लो। उन्होंने कहा कि हमें तीन गज जमीन चाहिए, तो उन्होंने कहा जहां कहीं

पर भी चाहिए, आप ले लो। अब वह विष्णु रूप में आ जाते हैं और एक गज में स्वर्गलोक आ जाता है एक गज में भू-लोक आ जाता है। फिर कहते हैं कि तीसरा कौन-सा है? अब तो महाबली का सिर ही बचा था और उस सिर के ऊपर पांव लगाकर उसको पाताल लोक भेजते हैं। ऐसा अतिथि आये, जो हमें पाताल लोक भेजने वाले हो, उसको हम "अतिथि देवो भव:" नहीं मानेंगे, यह बात मान लीजिए। हमारा आग्रह आपसे यही है कि आप इसके बारे में पुन: विचार करें, भारत की इज्जत रखें और इसकी रक्षा करें। शुक्रिया।

श्री रूद्रनारायण पणि (उड़ीसा): उपसभापति महोदय, येचुरी जी ने ईरान के मुद्दे पर जो बात कही है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...

Yes, Shri Kapil Sibal,

SHRI K. NATWAR SINGH (Rajasthan): Sir, I just want to make a correction. I am not speaking on it. Shri Sibal will speak.

Shri Sitaram Yechury mentioned that the Asian Relations Conference was held in March, 1947. Shrimati Sarojini Naidu presided it; Pandit Nehru was behind it and Gandhiji addressed it.

SHRI SITARAM YECHURY: The Preparatory Committee was formed in 1946.

SHRI NATWAR SINGH: That is right. But the meeting took place in March, 1947.

THE MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF OCEAN DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Mr. Deputy Chairman, Sir, I rise and consider it a privilege to participate and intervene in this debate. Sir, I am reminded of the famous words of Disraelli, when he said that nations have no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. And, I think, that is the only way that nations must conduct their foreign policies. And, it is in that context that I think the Prime Minister of India advisedly used the expression 'enlightened national interest'. I think the issue is not just of national interest, but enlightened national interest, because there are long-term implications; there are short-term implications. I go back to what Nehruji said in 1947. And, I quote. When he talked about foreign policy, he said, "Whatever policy you may lay down, the art of conducting the foreign affairs of a country lies in finding out what is most advantageous

to that country. We may talk about international goodwill and mean what we say, but in the ultimate analysis the Government functions for the good of the country it governs, and no Government dares to do anything which in the short and the long run is manifestly to the disadvantage of the country." Therefore, whether a country is imperialist, socialist or communist, its Foreign Minister thinks primarily of the interest of the country. And, I can state with a certain amount of confidence that that is exactly how we are moving forward.

Sir, if you look at the history of Indo-Iranian relations, really, they can be divided into three parts. After Independence till 1970 or 80, when there was the end of the Cold War; then, the new era began after 1990; and, then, of course, the recent events that took place after 2002. And, I dare say that Iran was on the side of the United States at that point in time, at the time of the Cold War. And we did not have the kind of bonhomie with Iran that developed after the end of the Cold War. After the Cold war, our relations with Iran became warmer, friendlier till, of course, what happened and what emerged pursuant to the events that took place in the IAEA because of certain satellite pictures that were shown, of the facilities in Iran, which, apparently, Iran did not report to the IAEA, for the last 16 years. I might also, for the record, state that despite the fact that Iran voted against us in many international forums, many a time, our relations with Iran, as a country, were not necessarily spoiled because of that; because countries act in their national interest; countries vote one way or the other in the context of their enlightened self-interest, and that does not destroy the overall macro picture. I might just indicate to you that Iran always failed to appreciate Indian anxieties regarding Kashmir in international forums, like the OIC, the United Nations Human Rights Commission. Iran was irked and adopted an anti-India posture in 1995 at the NPT Review Conference. Iran, unlike Algeria and Indonesia, repeatedly, backed resolutions in the OIC condemning alleged human rights abuses in Jammu and Kashmir. This did not spoil our relations with Iran. Iran voiced serious concern and was critical of the May 1998 events. We still did not spoil our relations with Iran. When Pakistan tested nuclear weapons, Iran said it was for their national security, and justified and tests by Paskistan. And, as far as India was concerned, it criticised India. We still did not spoil our relations with Iran. Iran moved a resolution in the United Nations in 2005 seeking universal compliance with the

3.00 P.M.

provisions of the Nuclear Non-Proliferation Treaty, despite objections by India; we did not still spoil our relations with Iran.

So, after so many votes by Iran against India without we spoiling our relationship, I do not understand, if we decide whether or not to vote one way or the other on the Iran issue on March 6, how it is going to spoil the relations between India and Iran.

The history of diplomacy is the history of nations taking positions in national interest, and I dare say that on March 6, as and when the matter comes up, we will take such a position. Now let us go back how this issue has arisen. It is not of our making. India did not sign the NPT. We considered the NPT a discriminatory international regime. That is our position even today. So, we did not sign the NPT, Israel did not sign the NPT, Pakistan did not sign the NPT. But Iran is a signatory to the NPT. Iran is not only a signatory to the NPT, Mr. Deputy Chairman, Sir, but Iran also entered into a safeguards agreement with the IAEA. Under that safeguards agreement, there are certain conditionalities that have to be complied with. There are certain disclosures that have to be made. There is certain prior information that has to be given. If they wanted to set up a nuclear conversion facility that information has to be given in advance. Even if not in advance, the information had to be given to the IAEA. If they wanted to import uranium hexafloride or uranium tetrafloride or uranium dioxide for the purposes of enrichment, that information had to be given. That is not our doing. We did not bring that matter up with the IAEA. Unfortunately, because of some satellite pictures that were taken and brought to the notice of Iran, this whole issue came up in 2002 and then IAEA decided to start communicating with Iran for the purposes of inspection. Iran was cooperating. In fact, I think, way back in December 2003, Iran decided that it would not resume its activities till such time this whole issue was decided. But while the inspections were going on, while the dialogue was going on with the IAEA, while the IAEA inspection teams went there, it was discovered that many things had been done without due notification under the safeguards agreement to the IAEA. Not only that there was a huge facility built underground in Natanz, one pilot facility for enrichment. There is another facility being set up which will be operational in a few years from now. Those facilities were not known to the IAEA. Then at Kalaye Electric Company which is another part of the

Iranian set up, some tests had gone on and inspections were conducted and it was found that there was contaminated material present. The IAEA is still trying to find out where that contaminated material came from. Sushmaji is right that some centrifuge components were found. It was also found that importation had been made and some P-2 drawings of centrifuge set-up were imported. And the villain of the piece was somebody in the neighbourhood. All that is factual and all that is known to everybody.

श्रीमती सुषमा स्वराज: बोलने में संकोच क्यों?

SHRI KAPIL SIBAL: I do give credit to Sushmaji that when the Prime Minister says that everybody knows where it came from, I think, Sushmaji has the intelligence to understand what that means. ...(*Interruptions*)... Sushmaji has the intelligence. ...(*Interruptions*)... Mr. Ahluwalia, of course, has got robust commonsense to understand that. ...(*Interruptions*)... Apart from intelligence. ...(*Interruptions*)... Apart from intelligence. I do not think we need to spell out these things. The fact of the matter is ...(*Interruptions*)... Even I am prepared to sit ...(*Interruptions*)... These are reports of the IAEA. I am referring to the June 19, 2003 report when the NDA was in power. I wonder why the NDA did not make an issue out of it. New facilities as of June 2003, were not known to the IAEA before – the Jabr Hayan Multipurpose Laboratory, fuel manufacturing plant, pilot fuel enrichment plant both at Natanz, fuel enrichment plant, Iran Nuclear Research Reactor. These were known to you. Why did you not raise the issue?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: We did.

SHRI KAPIL SIBAL: You knew where the import came from. Why did you not in this House make a statement that all this is being done with the help of particular neighbour whom you wish to name?

When you were in power and when you knew about these reports you kept mum. Sushmaji said that she was confused by the Prime Minister's statement. If she is confused, that has nothing to do with us. We can only try and help her out of her confusion and clarify issues. But I was confused at the end of her statement. I was totally confused because I did not know what she wanted us to do. She said on March 6th you should show flexibility. You should use diplomacy. She did not tell us how to vote. She hadn't made that clear on the floor of this House. She said, 'no, please tell us now, you have to tell us now. State whether we are to

vote for or against.' Please read her speech. So I was totally confused as to what the BJP position was.

श्रीमती सुषमा स्वराज: आप हैं ही कंफ्यूज्ड।

श्री कपिल सिब्बल: हां, हम तो हैं ही कंफ्यूज्ड, हम तो बिल्कुल हैं। लेकिन हमने तो नहीं कहा कि हम कंफ्यूज्ड हैं। ...(**व्यवधान**)... ऐसा है सुषमा जी, अब आप जरा गौर से सुनिए। मैं आपकी बातें ही रख रहा हूं।

It is very strange that a National Party, a responsible National Party refuses to take a position in this House. It should state to the nation what it wants. We are stating to the nation what we want. We are clear that if the situation so arises on March 6th that consistent with our national interest if a position has to be taken, we will take it. Luckily for us, I read in a newspaper report this morning about the Foreign Minister of Russia, Kiriyenko. There is some kind of an arrangement now where Iran has agreed, that there will be a facility on Russian territory where Uranium will be enriched. We are still not clear on the details. Once we are clear on the details and once we know the exact nature of that arrangement we will be in a better position to make a statement. But if that particular arrangements has been entered into and has been agreed upon, it is a very good step forward. That means the parties are negotiating. That means the parties are understanding each other's position. That means the parties are moving towards a consensus. That is what exactly India wants. I want to make it very clear that India wants to build that consensus. India does not want to take the extreme step of taking a position on that particular day. But, if a situation does arise that and has to be done and others are moving towards a vote we will then have to decide what we have to do. Certainly, whatever we will do we will be consistent with our national interest which is exactly what the Prime Minister has said. I want to go back to another issue. This issue came up for the first time in September and the issue came up in September because Iran in August took up the position that it was going to resume its Uranium enrichment activity. The whole issue came up in September. At that point in time we did not want a situation in which the matter would be referred to any other international body and a decision taken. We didn't want that. If you remember, much before February 4th when the latest vote took place, in September, we were the one's who intervened and said let this whole matter be decided in an hour within the IAEA. It is only on that condition

that we supported the Resolution. But come February, the situation entirely changed. Countries like Russia and China who in September were not in favour, voted for the resolution. Countries like Egypt, countries like Brazil, countries like Sri Lanka, they all voted for the resolution. Yechuryji pointed out about Non-aligned countries. There were 16 Non-aligned countries. Eight voted for the Resolution. Three against the Resolution, *i.e.* Syria, Venezuela and Cuba and then five other abstained. So, 8- for, 5 - abstained, 3 - against. So, even in the NAM, there was no consensus. A lot of NAM countries voted for the Resolution. The reason is, the Prime Minister has said so in his Statement. 'We do not want a bomb in our neighbour; we certainly do not want basement bombs to erupt anywhere'. We are cognizant of the threat of terrorism and the BJP has been cooperating with us, with the international community. We have been the victims of the onslaughts of terrorism. We do not want those bombs. We do not want that the technology given by A. Q. Khan be easily available to terrorist groups to be used at any time, on any of us. Our position is to protect ourselves. And we believe entirely and completely in non-proliferation. That is our position. The Prime Minister said so even in the United States. He made a statement that as far as India is concerned, we want to see the end of the use of nuclear weapons in this world and we stand by that. That was Rajiv Gandhi's plan, that was Rajiv Gandhi's dream and we stand by that dream. We want to, in fact, fulfil it. But the fact is, that we cannot barter our national security, our national interest and allow basement bombs to proliferate in our neighbourhood. That is exactly what might happen. We have complete faith in the Iranian people. We want and, I think, it is important to state, and I want to state it now that we fully respect the soveriegnty of the Iranian Government to develop nuclear technology for peaceful purposes. If they want nuclear energy for peaceful purposes, I think, they have the sovereign right to do so. But they have bound themselves, pursuant to the NPT, to IAEA safeguards. And having bound themselves, they are bound to comply with those safeguards. And, if, we, as a country, say that they need not comply with them, then, we will be, in fact, denouncing an international regime to which we are a party. How can we say that a country, which is part of the NPT, should violate the NPT? How can we say that a country, which has signed the Safeguards Agreement, should violate the Safeguards Agreement? We cannot say that. And, therefore, we want Iran to comply with its obligations. We also want the EU-3 Resolution to be cognisant of

Iran's needs, to be in cognisant of their desires and their sovereignty and in that context, through consensus, come to an arrangement through which Iran's sovereign rights are maintained; and, at the same time, the international non-proliferation regime is also not jeopardised. That is, exactly the position that India is going to take.

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Mr. Sibal, will you please yield for a minute?

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, I am ready to yield.

SHRI NILOTPAL BASU: You were consantly referring to basement bombs and Iran having a bomb.

SHRI KAPIL SIBAL: I did not say that. ...*(Interruptions)*... I want to make it clear and at no stage have I said that. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: So far as we are concerned, till the IAEA Director General's Report is there, there is nothing conclusive. You may please clarify that ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Yes, I will.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He said, "We don't want."

SHRI KAPIL SIBAL: I never said that. ...*(Interruptions)*... Let me, Sir, again say this. This is a June 19, 2003 Report. Let me inform you of the conclusions of the IAEA. This is the first point. '(a) Failure to declare the import of natural uranium in 1991, and its subsequent transfer for further processing.' It is not our conclusion. Now, either you say on the floor of this House, you disagree with this, or that India should stand up and disagree with this. ...*(Interruptions)*... Now, one second. ...*(Interruptions)*... Mr. Nilotpal Basu, let me finish ...*(Interruptions)*... Let me complete ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: So far as the NPT is concerned, it does not ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: You asked me, "What is the basis?" On 15th April, 2003, Iran submitted ICRs with regard to import of UO-2, which is Uranium Dioxide, UF-4 Uranium Tetra Floride, UF-6. Iran has still to submit ICRs transfer of material for further processing. (C) Iran's failure to declare the facilities where such material (including the waste) was received, stored and processed. Iran's failure in a timely manner information on

the waste storage at Eshfahan, and another, Iran's failure ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: That is not my question. My question is whether the IAEA has come to this conclusion that Iran possesses a bomb or not. You were referring to ...*(Interruptions)*... That is my specific question ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He has not said that ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: I never said that ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kapil Sibal, Mr. Bimal Jalan wants to say something, if you kindly yield.

DR. BIMAL JALAN: (Nominated) Mr. Deputy Chairman, Sir, let me clarify that I do not have any fixed view on this matter. I am listening to it. I have no expertise on it, but one point I want a clarification, on which the hon. Minister said that Iran is a signatory to the NPT, and they are violating the terms of the NPT, which they should not be doing. I understand that. But the question is, supposing, for argument's sake, hypothetically, if Iran was doing exactly what it is doing, but if it was not a signatory to the NPT, what would be our position in the national interest?

SHRI KAPIL SIBAL: Well, I think, our position is our position on India.

DR. BIMAL JALAN: No; no. I am asking you, if Iran was not a signatory to the NPT and not signed the NPT, what would be our position in the national interest?

SHRI KAPIL SIBAL: I don't think I need to answer a hypotehtical question. As far as Mr. Basu's intervention is concerned, I never said that Iran possesses nuclear weapons. I never said that. Far be it from me to say this — this is what the IAEA says, not me — but, most of the things that I have said are not my conclusions, but conclusions of the IAEA, "that it will take several years for Iran to, actually, develop nucelar weapons". That is the IAEA's conclusion, not mine. I did not say that. I said that we do not want basement bombs. That is all. That this technology, which is now with Iran, if it is exported, it somehow gets into the hands of undesirable elements in Iran's neighbourhood — isn't our national security in jeopardy? I think that this House will in unison stand up and say that we must, at all costs, avoid a situation when our own people are subject to this kind of jeopardy.

That is the point . That is the only issue ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): How can you ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is his view ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Unfortunately, Sir, this is the same argument we heard in this House when there were calls ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Basu, that is his view. Please listen to him.

SHRI NILOTPAL BASU: ...for sending our troops to Iraq, because Iraqis were, then, supposed to have a bomb ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Deputy Chairman, Sir, the point I wish to make now — and I think that I have said enough — is, we are in a very fluid situation. As I said, from the newspaper report that I have read this morning, the situation continues to be fluid. In this fluid situation, we will be looking at the situation very carefully. We will see the pros and cons, and as and when the issue arises for discussion on the 6th of March, we will, then, consistent with our larger, national interset and enlightened national interest, enlightened self-interest, decide which way we will vote. E ıt, I will assure this House that we are for ocnsensus. I assure this House that we want to ensure that this matter remains within the IAEA.

SHRI DIPANKAR MUKEHRJEE (West Bengal): Correct.

SHRI KAPIL SIBAL: No, we want to. Whether we can or cannot is not in our hands; it is not our resolution. It is the resolution of the Eu-III. *(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: It is not like कौन बनेगा करोड़पति that at the last moment, I will push the button...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Even if, we were to — if you don't mind ...*(Interruptions)*... take a position ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not yielding ...*(Interruptions)*... He is not yielding...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKEHRJEE: It is not like कौन बनेगा करोड़पति ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: We did not interfere while you were making your points. I never interfered ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Our point is very clear ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: I know your point. Unfortunately ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Please tell us specifically whether you are going to abstain; then this should be the national consensus. If they can join us, let them say they will abstain. Then, there will be consensus here. Let it not be like Kaun Banega Crorepati, that at the last moment, you will push the button.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dipankar Mukherjee, Mr. Kapil Sibal has not yielded.

SHRI KAPIL SIBAL: Whether we will abstain or not abstain, whether we will vote or not ...*(Interruptions)*...

श्री दीपांकर मुखर्जी: गवर्नमेंट पीपुल से बनती है, गवर्नमेंट आसमान से आती है क्या! गवर्नमेंट आसमान से नहीं आती है, गवर्नमेंट यहाँ से बनती है ...(**व्यवधान**) ... आप क्या चाहते हैं, बोलिए? ...(**व्यवधान**) ...

श्री उपसभापति: पाणि जी, आप बैठिए ...(**व्यवधान**) ...

श्री दीपांकर मुखर्जी: हम तो बोल रहे हैं कि एबस्टेन करना चाहिए ...(**व्यवधान**) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dipankar Mukherjee, let him speak ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Deputy Chairman, Sir, in this heat, I am reminded of the words of John F. Kennedy. This is what he said on Foreign Policy. He said, "The purpose of Foreign Policy is not to provide an outlet for our own sentiments of hope, or, indignation; it is to shape real events in a real world." And, I assure this House that when that real world situation arises, we will shape the real events. Thank you.

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): चैयरमेन साहब, कपिल सिब्बल साहब ने अपनी तकरीर में कम-से-कम आधा दर्जन बार "एनलाइटंड" वर्ड का इस्तेमाल किया। मुझे खुशी है, वह बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत तेजी से इस शब्द का उपयोग सीख रहे हैं। मैंने अभी मुशर्रफ साहब की स्पीच सुनी थी। उन्होंने भी कम-से-कम दर्जन बार "एनलाइटंड" शब्द का इस्तेमाल किया था। तो दोनों की, जैसे सुषमा जी ने कहा था, एक सोच है। कहीं बोध ट्री है जहां से यह आ

रही है, लेकिन एक बात इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि we have neither permanent friends, nor permanent enemies. We have permanent national interest. तो मैं सिर्फ इस पर बात करना चाहूंगा कि क्या हमारे हित में है, यह वोट? क्या यह भारत के हित में है वोट? मैं इस में नहीं जाना चाहूंगा कि ईरान से हमारी दोस्ती कैसी थी? ईरान ने हमारे लिए कितनी बार वोट किया, कितनी बार नहीं किया? हम ईरान को क्या सबक सिखाना चाहते हैं? मैं इस में नहीं जाना चाहूंगा कि हम नॉन-अलाइंड थे और पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? मैं इस में भी नहीं जाना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी ने ओल्फ पॉल्मे के साथ मिलकर क्या पॉलिसी रखी थी, न्यूक्लिअर डिसआर्मामेंट की, उसमें भी मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं खाली इस सवाल पर जाना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्र हित में क्या है? क्या यह भारत के राष्ट्रीय हित में है?

सर, एक मुहावरा सुनते आए हैं कि, ''स्टिक एंड कैरॉट''। मैं यहां पर स्टिक एंड कैरॉट की कहानी में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारे सामने भी एक गाजर लटकाई गई है। भारत के सामने एक गाजर लटकाई गई है और वह न्यूक्लिअर एग्रीमेंट की गाजर लटकाई गई है। हम बहुत बड़ी इकॉनोमिक पावर बनने वाले हैं। बस, हमें इतना करना है कि हम अमेरिका के रास्ते पर चल पड़ें। हमें सपने दिखाए गए हैं कि हम इकॉनोमिक पावर बनने वाले हैं। शायद हम दुनिया की, अमेरिका से भी बड़ी इकॉनोमिक पावर बन जाएंगे। यह अमेरिका के थिंक टैंक हमें बता रहे हैं और हम गदगद हुए जा रहे हैं। अब इस गाजर के साथ-साथ डंडे का भी इस्तेमाल हो रहा है। हमने पहले डंडे का इस्तेमाल देखा जब प्रधान मंत्री ने अमेरिका जाने के बाद वहां हमारी जो डिफेंस डील थी ''फ्रेमवर्क एग्रीमेंट'', उस के साइन करने के अगले दिन हमारे मणिशंकर जी के मुंह पर कालिख पोत दी और कह दिया कि गैस पाइप लाइन संभव नहीं है। उन्होंने वहां पर कहा था कि ईरान के साथ गैस पाइप लाइन संभव नहीं है। उस दिन लगता था और उसी दिन हमारे कान खड़े हो गए थे। हमें पता लग गया था कि क्या होने वाला है, हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। उस के बाद गाजर लटकती है और डंडा चलता है। कभी कोई कांग्रेस मेन हमें धमकी देता है कि अगर ईरान पर वोट नहीं दिया तो हमें उस का सबक सिखाया जाएगा, हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हमने यह वोट अपने राष्ट्रीय हित में डाला है। हमने अमेरिकन कांग्रेस के डरावे में आकर नहीं डाला है। कभी हमें एम्बैसेडर मलफोर्ड साहब धमकी देते हैं, लेकिन हमने मलफोर्ड साहब से डरकर यह वोट नहीं दिया है। हमने तो यह वोट राष्ट्र के हित में दिया है, भारत के हित में दिया है। कभी वहां की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की बात होती है, कभी उन को कहा जाता है "Ayatullahs of non-proliferation" वह हम को धमकियां देते हैं और हिंदुस्तान से साफ कहते हैं कि ''कैपिंग'' करनी होगी यानी कि आप को न्यूक्लिअर आर्म्स बनाने बंद करने होंगे, लेकिन हम उनसे नहीं डरते। हम राष्ट्र के हित में, भारत के हित में यह फैसला करते हैं और वोट डालते हैं। मैं आप से

जानना चाहता हूं कि भारत के हित में जो हम वोट डाल रहे हैं, मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा, दो दिन पहले न्यूयार्क टाइम्स का एडीटोरियल है, जिस में कहा गया है कि India's vote on Iran is a victory for Mr. Bush, यह न्यूयार्क टाइम्स कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं "with its eye on the nuclear deal, India recently bowed to American pressure and cast its vote at the International Atomic Energy Agency to refer Iran's suspected nuclear programme to United Nations Security Council." यह न्यूयार्क टाइम्स कह रहा है। Hindustan succumbed to the American pressure. यह मैं नहीं कह रहा हूं और हम उस के बावजूद कहते हैं कि हमारा वोट राष्ट्र हित में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हमारे राष्ट्र हित में है कि ईरान का वही हश्र हो जो ईराक का किया गया। हमें बताया गया कि एक आदमी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। उस को मिटाने के लिए, एक आदमी को मिटाने के लिए अफगानिस्तान को ''स्टोन एज'' में पहुंचा दिया गया। हजारों, लाखों लोगों को मार दिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया। वह आदमी आज भी जिंदा है। हम से कहा गया कि हमारे साथ आओ, हमारे पीछे आओ, दुनिया से कहा गया क्योंकि पूरी दुनिया को सद्दाम हुसैन से खतरा है। weapons of mass destruction से पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, अगर सद्दाम हुसैन को नहीं मिटाया गया और रिजीम चेंज नहीं हुई। सर, सद्दाम हुसैन को कैद किया गया, इराक में आज भी खून बह रहा है। वहां हजारों, लाखों मारे गए हैं। हमारा उस से कोई लेना-देना नहीं है। वहां लोग मारे गए, लेकिन कहां हैं weapons of mass destruction. हम तो यह कहते हैं। when they came for Afghanistan, we said, "so what, we are not Afghanistan." When they came for Iraq, we said, "so what, we are not Iraq." When they came for Iran, we said, "so what, we are not Iran!" When they come for us, there would be nobody to help us. हम एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं, हम एक ऐसा situation क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें कल हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारी आर्ग्यूमेंट्स हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगी, सर।

सर, आज हम अखबार में पढ़ रहे हैं कि हमारे साइंटिस्ट को, ऑर्डिनरी साइंटिस्ट को यह कह कर वीज़ा नहीं दिया जाता कि वे कोई कैमिकल वैपनरी के साथ जुड़े हुए हैं। सारी दोस्ती, सारी मोहब्बत और हम सारे जो गले लग रहे हैं, उसके बाद भी आज हमारे साइंटिस्ट को वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। कल इस बात की क्या गारंटी है कि वे कहेंगे कि आपके बच्चों के लिए दूध बनाने की फैक्टरी, जैसी सूडान में थी, उसमें कैमिकल वैपन नहीं बन रहे हैं? क्या उस पर मिसाइल नहीं गिरा दिए जाएँगे? सूडान में गिराए गए, जबकि टैस्ट में कुछ नहीं मिला। किसी ने सौरी तो नहीं कहा। हमने भी नहीं कहा। हम भी खुश होते रहे कि सूडान पर गिराया है, हमारा क्या है? लेकिन क्या कल को यह हमारे साथ नहीं हो सकता? अगर आज हमारे साइंटिट पर यह डाउट खड़ा किया जा रहा है, सर तो क्या यह हमारे हित में है? हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की

सेक्योरिटी की बात करते हैं। हम कहते हैं कि न्यूक्लीयर डील करके हम यह अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की सेक्योरिटी करने के लिए कर रहे हैं।

सर, यहाँ पर लोगों ने बताया। बड़ी स्पष्ट बात है, साफ बात है कि आज हमारी 3 प्रतिशत इनर्जी नीड्स न्यूक्लियर एनर्जी से पूरी होती हैं। कल को हम यह कितना कर लेंगे, छः प्रतिशत कर लेंगे? लेकिन, हमारी एनर्जी नीड्स तो इसी वैस्ट एशिया से आने वाली है, इन्हीं अरब कन्ट्रीज़ से आने वाली है और हमारा रवैया क्या है? हम इज़राइल के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं, मुँह खोलने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा आक़ा नाराज हो जाएगा। हम क्यों इज़रायल के खिलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते? यह खुली बात है, सब को मालूम है कि इज़रायल ने 200 बम्ब बनाए हैं। अगर इतनी ईमानदारी है, अगर इतनी ही ईमानदारी से यह सरकार चल रही है, अगर यही ईमानदारी इराक़ के बारे में थी, यही अफगानिस्तान के बारे में थी, यही ईरान के बारे में है—हम तो बड़े ईमानदार लोग हैं। हम तो आई॰ए॰ई॰ए॰ की रिपोर्ट के ऊपर जाते हैं। हम तो कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं। हमारा देश तो आई॰ए॰ई॰ए॰ की रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहा है। रिपोर्ट तो इजरायल के बारे में भी मौजूद है। तब हममें इजरायल का नाम लेने की हिम्मत क्यों नहीं है? क्या इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मुतास्सिर नहीं होगी। क्या हमारी doorsteps पर एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है कि जहाँ आज हमला करने की तैयारियाँ हैं, खुले आम कहा जा रहा है, इजरायल को उकसाया जा रहा है और उसे अमेरिका की तरफ से लेटेस्ट मिसाइल दिए गए हैं। ये मिसाइल अन्दर तक पेनेट्रेट कर सकते हैं। इनका परपज़ यह कहा जा रहा है, अमेरिकन प्रेस यह कह रहा है, कि इनका परपज़ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय करना है। पैसा दिया जा रहा है। रिज़िम चेंज की बात हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की पॉलिसी क्या होगी, अगर इज़रायल कल या अगले दो महीने के अन्दर या छः महीने के अन्दर ईरान के न्यूक्लियर साइट के ऊपर अटैक कर देता है और वार की एक situation बन जाती है? हमारी एनर्जी नीड्स का क्या होगा? भारत के डेवलपमेंट का क्या होगा? इसलिए इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

आप भारत के enlightened self-interest की बात करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह enlightened self-interest है, सर। ये कहते हैं कि ईरान से खतरा है। ईरान बेसमेंट बम्ब बनाने की तरफ जा सकता है। जैसा कि एक सवाल सुषमा जी ने उठाया था और मैं भी उठाना चाहता हूँ कि अगर किसी ने ईरान को न्यूक्लियर प्लान्स दिये, तो वह देश कौन-सा था? क्या वह पाकिस्तान नहीं था? क्यों हमारे प्रधान मंत्री जी उसका नाम लेने को तैयार नहीं हैं? अमेरिका के सामने न लें, इस पार्लियामेंट के अदर तो उसका नाम ले लें। क्या यहाँ पर भी डर है? हमारे ऊपर अमेरिका का इतना खौफ है कि हम पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते, जबकि हमें खतरा ईरान से नहीं है! हम इम्पोर्टर को तो सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्ट कर रहा है,

जो उसको भेज रहा है, जो प्लान्स दे रहा है, जो बेच रहा है और जो बांट रहा है, उसके खिलाफ हम एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमारी हिम्मत नहीं कि बोल सकें। क्यों? क्योंकि चचा सैम, अंकल सैम मुझसे ऐसा नहीं चाहते। तो सर, यहां पर बात किसी न्यूक्लियर आर्म्स की नहीं है। खुद सी॰आई॰ए॰ की रिपोर्ट्स कह रही हैं कि "Iran is ten years away from any nuclear armament." वह अभी दस साल दूर है। आई॰ए॰ई॰ए॰ यह कह रहा है कि हमें अभी इस तरह का कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है कि वे न्यूक्लियर फ्यूल एनरिच कर रहे हैं। आई॰ए॰ए॰ ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। उसके बाद भी हम अमेरिका के पीछे-पीछे ताली बजा रहे हैं।

असल बात यह है, इंग्लैंड का ''न्यू स्टेट्समैन'', यह कहता है कि 'Like the invasion of Iraq, an attack on Iran has a secret agenda that has nothing to do with the Tehran regime's imaginary Weapons of Mass Destruction. That Washington has managed to coerce enough members of the International Atomic Energy Agency—नोट कीजिए सर, Washington has managed to coerce enough members of the International Atomic Energy Agency—into participating in a diplomatic charade is no more than reminiscent of the way it intimidated and bribed the "International community" into attacking Iraq in 1991.

Iran offers no "nuclear threat". There is not the slightest evidence that it has the centrifuges necessary to enrich uranium to weapons-grade meterial. The head of the IAEA, Mohamed El Baradei, has repeatedly said his inspectors have found nothing to support American and Israeli claims. Iran has done nothing illegal; it has demonstrated no territorial ambitions nor has it engaged in the occupation of a foreign country, unlike the United States, Britain and Israel. It has complied with its obligations under the Non-Proliferation Treaty to allow inspectors to "go anywhere and see anything", unlike the US and Isreal. The latter has refused to recognise the NPT, and has between 200 and 500 thermonuclear weapons targeted at Iran and other Middle Eastern State.

सर, यह जो सिचुएशन है, इसमें हम भारत को आज कहां लाकर खड़ा कर रहे हैं हम क्या बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? कहा यह जाता है कि पांच कंट्रीज ने जब वोट किया, तो हमने भी साथ में वोट किया। मैं जानना चाहता हूं कि कहां भेजने के लिए वोट किया? क्या सिक्योरिटी कौंसिल में भेजने के लिए वोट किया या आइ॰ए॰ई॰ए॰ सिक्योरिटी कौंसिल में भेजने के लिए वोट किया? क्या सिक्योरिटी कौंसिल में भारत की आवश्यकता है, क्या वहां भारत की कोई शह है, क्या भारत की कोई पोजीशन है? हम वहां भेजना चाहते हैं, जहां हमारी शह नहीं है, जिसके

हम परमानेंट मैम्बर थे, ओरिजनल मैम्बर थे, फाउंडर मैम्बर थे, वहां से हम इश्यू को निकाल देना चाहते हैं। क्यों नहीं हम इस इश्यू को यहां रखना चाहते? हम इश्यू को सिक्योरिटी कौंसिल में क्यों भेजना चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि हम फाइव पावर को फॉलो कर रहे हैं। फाइव पावर आपको अपने दरवाजे में नहीं घुसने देती, आपको अपनी चौखट के बाहर खड़े रखती है। जब आप कहते हैं कि हमारा अधिकार है, हम सबसे बड़ी डेमाक्रेसी हैं, हम इतना बड़ा देश हैं, तो आपको आपकी हैसियत बता दी जाती है। बार-बार यह हो रहा है। उसके बाद भी हम बड़े खुश हैं और मीडिया के जरिए मिडल क्लास के अंदर यह फैलाया जा रहा है कि देश का हित इसमें है, एक बहुत बड़ी इकोनोमिक पावर हम बनने वाले हैं, सारे देश में दूध की नदियां बहेंगी, हम गोल्डन बर्ड बन जाएंगे, विश्व में सोने की चिड़िया होंगे, हम इकोनोमिक पावर नंबर एक होंगे या नंबर दो होंगे। इसमें चीन पहले होगा या हम पहले होंगे, लेकिन अमरीका से तो पहले आगे हम होंगे ही होंगे।

श्री उपसभापति: आप कनक्ल्यूड करें, प्लीज।

श्री शाहिद सिद्दिकी: यह कौन फैला रहा है? यह अमरीका से फैलाया जा रहा है और हम बड़े खुश हैं कि बस इतना सा करना है कि अमरीका के पीछे-पीछे चलो, अमरीका से दोस्ती कर लो, अमरीका के हित को पूरा कर दो। इसी हित को लेकर चला जा रहा है।

सर, बहुत सी बातें हैं कहने को, मगर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी एक बार मैं, दिनेश जी और हमारे काफी मैम्बर्स वाशिंगटन गए थे। हमारा एम॰पीज॰ का डेलीगेशन गया था। हमने कंडोलीजा राइस से भी बात की, स्टेट डिपार्टमेंट से बात की और अपने पाइंट् ऑफ व्यूज रखे। जब हम ट्रेन में बैठकर वाशिंगटन से न्ययार्क वापस जा रहे थे, उस समय मेरे साथ दिनेश त्रिवेदी जी भी थे। जो टिकट चेक करने वाला था, वह ब्लेक मेन, हैंडसम, मिडिल एज्ड मेन था, उसने आकर हमारा टिकट चेक किया और खामोशी से चला गया। जब हम उतरने लगे, उसने हल्के से आकर पूछा Are you Members of Parliament from India? I said, "Yes, how do you know?" He said, "The Security Head informed me. "I said, "Good." He said, "I am extremely disappointed in India." I was taken aback. I said, "Why are you disappointed in the India." He said,, "We never expected this from India that India will vote against Iran. We are extremely disappointed." I was Shocked. एक आदमी, टिकट चेकर, जिसका कोई पोलिटिकल कैरियर नहीं, वह आकर हमसे यह कह रहा है।I am extremely disappointed in India. Let me tell you, today the people of Africa, Asia, Latin America and the people of the world are disappointed in our country. There was a time when we led the people of the world. Today we are disappointed; people of India are disappointed because of a policy which is totally not based on any morality, not based on any ideology, not based

on any principle and not based on any international law, and still we claim that what we are doing is the enlightened national interest. खुदा इस एनलाइटेंड नेशनल इंटरेस्ट से हिन्दुस्तान को बचाकर रखे। यह मेरी दुआ है और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह वोट 6 तारीख का आप करेंगे, हो सकता है कि इसको कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए, मगर आप वोट करेंगे, तो मेरी पार्टी इस वोट का पूरा विरोध करेगी, क्योंकि हम समझते हैं कि यह भारत के हित में नहीं है, भारत के हित को अमरीका के हित के लिए सेक्रिफाइज किया जा रहा है, यह अमरीका के हित में है। अगर ऐसा होगा, तो हम मजबूर होंगे इस सरकार के खिलाफ नो कांफीडेन्स मोशन लाने के लिए, क्योंकि यह सरकार भारत के हित के खिलाफ काम करेगी। धन्यवाद।

†[شری شاہد صدیقی ''اتر پردیش'' : چیرمین صاحب، کپل سبل صاحب نے اپنی تقریر میں کم سے کم آدھا درجن بار ''اینلائٹنڈ'' ورڈ کا استعمال کیا۔ مجھے خوشی ہے، وہ بہت اچھے اسٹوڈینٹ ہیں اور بہت تیزی سے اس شبد کا اُپیوگ سیکھ رہے ہیں۔ میں نے ابھی مشرف صاحب کی اسپیچ سنی تھی۔ انہوں نے بھی کم سے کم درجن بار ''اینلائٹنڈ'' شبد کا استعمال کیا تھا۔ تو دونوں کی، جیسے سشما جی نے کہا تھا، ایک سوچ ہے۔ کبھی بودوڑی ہے جہاں سے یہ آ رہی ہے، لیکن ایک بات انہوں نے بری اہم کہی ہے کہ We have neither permanent friends, nor permanent enemies. We have perrmanent national interest. تو]†

†[میں صرف اس پر بات کرنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے ہت میں ہے، یہ ووٹ؟ کیا یہ بھارت کے ہت میں ہے ووٹ؟ میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا کہ ایران سے ہماری دوستی کیسی تھی؟ ایران نے ہمارے لئے کتنی بار ووٹ کیا، کتنی بار نہیں کیا؟ ہم ایران کو کیا سبق سکھانا چاہتے ہیں؟ میں اس میں بھی نہیں جانا چاہوں گا کہ ہم نان الائنڈ تھے اور پنڈت جواہر لال نہرو جی نے کیا کہا تھا؟ مہاتما گاندھی جی نے کیا کہا تھا؟ میں اس میں بھی نہیں جانا چاہوں گا کہ راجیو گاندھی جی نے اولف پالمے کے ساتھ مل کر کیا پالیسی رکھی تھی؟ کیا نیوکلیئر ڈِسارمامنٹ کی، اس میں بھی میں جانا چاہوں گا۔ میں خالی اس سوال پر جانا چاہوں گا کہ ہمارے راشٹریہ ہت میں کیا ہے؟ کیا یہ بھارت کے راشٹریہ ہت میں ہے؟]†

†[]Transiteration in Urdu Script.

سر، ایک محاورہ سنتے آئے ہیں کہ ''اسٹک اینڈ کیراٹ''۔ میں یہاں پر اسٹک اینڈ کیراٹ کی کہانی میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ہمارے سامنے بھی ایک گاجر لٹکائی گئی ہے۔ بھارت کے سامنے ایک گاجر لٹکائی گئی ہے اور وہ نیوکلیئر انگیجمینٹ کی گاجر لٹکائی گئی ہے۔ ہم بہت بڑی اکانومی پاور بننے والے ہیں۔ بس، ہمیں اتنا کرنا ہے کہ ہم امریکہ کے راستے پر چل پڑیں۔ ہمیں سپنے دکھائے گئے ہیں کہ ہم اکانومی پاور بننے والے ہیں۔ شاید ہم دنیا کی، امریکہ سے بھی بڑی اکانومی پاور بن جائیں گے۔ یہ امریکہ کے تھنک ٹینک ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم گدگد ہوئے جا رہے ہیں۔ اب اس گاجر کے ساتھ ساتھ ڈنڈے کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے ڈنڈے کا استعمال دیکھا جب پردھان منتری نے امریکہ جانے کے بعد وہاں ہماری جو ڈِفینس ڈیل تھی ''فریم ورک اگریمنٹ'' اس کے سائن کرنے کے اگلے دن ہمارے منی شنکر جی کے منہ پر کالک پوت دی اور کہہ دیا کہ گیس پائپ لائن سمجھو نہیں ہے۔ انہوں نے وہاں پر کہا تھا کہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن سمجھو نہیں ہے۔ اس دن لگتا تھا اور اسی دن ہمارے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد گاجر لٹکتی ہے اور ڈنڈا چلتا ہے۔ کبھی کوئی کانگریس مین ہمیں دھمکی دیتا ہے کہ اگر ایران پر ووٹ نہیں دیا تو ہمیں اس کا سبق سکھایا جائے گا، ہمیں سزا بھگتنی پڑے گی۔ لیکن ہم نے یہ ووٹ اپنے راشٹریہ ہت میں ڈالا ہے۔ ہم نے امریکن کانگریس کے ڈراوے میں آ کر نہیں ڈالا ہے۔ کبھی ہمیں ایمپیچڈ رلفوڈ صاحب دھمکی دیتے ہیں، لیکن ہم نے ملفوڈ صاحب سے ڈر کر یہ ووٹ نہیں دیا ہے۔ ہم نے تو یہ ووٹ راشٹریہ ہت میں دیا ہے، بھارت کے ہت میں دیا ہے۔ کبھی وہاں کی فارن افیئرس کمیٹی کی بات ہوتی ہے، کبھی ان کو کہا جاتا ہے ['Ayatullah's of non-proliferation' [وہ ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں اور ہندوستان سے صاف کہتے ہیں کہ'' کیپنگ'' کرنی ہوگی یعنی کہ آپ کو نیوکلیئر آرمس بنانے بند کرنے ہوں گے، لیکن ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ ہم راشٹر کے ہت میں، بھارت کے ہت میں یہ فیصلہ کرتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بھارت کے ہت میں جو ہم ووٹ ڈال رہے ہیں؟ میں یہاں پر کوڈ کرنا چاہوں گا۔ دو دن پہلے نیویارک ٹائمز کا ایڈیٹوریل ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ [India's vote on 'With its eye on Iran is a victory for Mr. Bush.] [یہ نیویارک ٹائمز کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔]

the nuclear deal, India recently bowed to American pressure and cast its vote at the International Atomic Energy Agency to refer Iran's suspected nuclear program to the United Nations Security Council'. Hindustan succumbed to the [ ] یہ نیویارک ٹائمز کہہ رہا ہے۔ American pressure. [ ] یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اور ہم اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ راشٹریہ ہت میں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ہمارے راشٹریہ ہت میں ہے کہ ایران کا وہی حشر ہو جو عراق کا کیا گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ ایک آدمی پوری دنیا کے لئے خطرہ ہے۔ اس کو مٹانے کے لئے، ایک آدمی کو مٹانے کے لئے افغانستان کو 'اسٹون ایج' میں پہنچا دیا گیا۔ ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا، اسے برباد کر دیا گیا۔ وہ آدمی آج بھی زندہ ہے۔ ہم سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے پیچھے آؤ، دنیا سے کہا گیا کیوں کہ پوری دنیا کو صدام حسین سے خطرہ ہے [ ] weapons of mass destruction سے پوری دنیا برباد ہو جائے گی، اگر صدام حسین کو نہیں مٹایا گیا اور ریجم چینج نہیں ہوئی۔ سر، صدام حسین کو قید کیا گیا، عراق میں آج بھی خون بہہ رہا ہے۔ وہاں ہزاروں، لاکھوں مارے گئے ہیں۔ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہاں لوگ مارے گئے، لیکن کہاں ہے [ ] weapons of mass destruction ہم تو یہ کہتے ہیں۔ when they came for Afghanistan, we said, "So what, we are not Afghanista". When they came for Iraq, we said, "So what, we are not Iraq. When they came for Iran, we said, 'so what, we are not Iran!" When they come for us, there would be nobody to help us. ہم ایک ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں، ہم ایک ایسا سچویشن کریٹ کر رہے ہیں، جس میں کل ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ساری آرگیومنٹ ہمارے خلاف استعمال ہونگی، سر، آج ہم اخبار میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے سائنٹسٹ کو، آرڈنری سائنٹسٹ کو یہ کہہ کر ویزا نہیں دیا جاتا کہ وہ کوئی کیمیکل ویپنری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ساری دوستی، ساری محبت اور ہم سارے جو گلے لگ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آج ہمارے سائنٹسٹ کو ویزا نہیں دیا جا رہا ہے۔ کل اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ کہیں گے کہ آپ کے بچوں کے لئے دودھ بنانے کی فیکٹری، جیسی سوڈان میں تھی، اس میں کیمیکل ویپن نہیں بن رہے ہیں؟ کیا اس پر میزائل نہیں گرا دئے جائیں گے؟ سوڈان میں گرائے گئے، جب کہ ٹسٹ میں کچھ نہیں ملا۔ کسی نے سوری تو نہیں کہا۔ ہم نے بھی نہیں کہا۔؛

ہم بھی خوش ہوتے رہے کہ سوڈان پر گرایا ہے، ہمارا کیا ہے؟ لیکن کیا کل کو ہمارے ساتھ نہیں ہوسکتا؟ آج اگر آج ہمارے سائنٹسٹ پر یہ ڈاؤٹ کھڑا کیا جارہا ہے، سر۔ ہمارے ہت میں ہے یہ؟ ہم اپنی نیوکلیئر انرجی کی سیکورٹی کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیل کرکے ہم نیوکلیئر اینرجی، جو ہے اس کی اپنی سیکورٹی کرنے کے لئے کررہے ہیں۔ سر، یہاں پر لوگوں نے بتایا۔ بڑی واضح بات ہے، صاف بات ہے کہ ۳ فیصد آج ہماری انرجی نیڈس نیوکلیئر انرجی سے پوری ہوتی ہیں۔ کل کو ہم یہ کتنا کرلیں گے، چھ فیصد کرلیں گے۔ لیکن ہماری انرجی نیڈس تو اسی ویسٹ ایشیا سے آنے والی ہے۔ انہیں ارب کنٹریز سے آنے والی ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اسرائیل کے خلاف ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہیں، منہ کھولنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ ناراض ہوجائے گا، کیونکہ ہمارا آقا ناراض ہوجائے گا۔ کیوں ہم ایک لفظ نہیں بول سکتے، اسرائیل کے خلاف؟ اسرائیل کھلا ہے، سب کو معلوم ہے۔ ۲۰۰ بم بنائے ہیں، اس نے۔ اگر اتنی ہی ایمانداری ہے، اگر اتنی ہی ایمانداری سے یہ سرکار چل رہی ہے، اگر یہی ایمانداری عراق کے بارے میں ہے۔ ہی افغانستان کے بارے میں ہے۔ یہی ایران کے ابارے میں ہے۔ ہم تو بڑے ایماندار لوگ ہیں۔ ہم تو آئی اے ای اے کی رپورٹ کے اوپر جاتے ہیں۔ ہم تو کوئی ہوا میں بات نہیں کررہے ہیں۔ ہمارا دیش تو آئی اے اے کی رپورٹ کے اوپر بات کررہا ہے۔ تو رپورٹ تو موجود ہے، اسرائیل کے بارے میں بھی۔ ہم میں کیا ہمت نہیں ہے، اسرائیل کا نام لینے کی۔ کیا اس سے ہماری انرجی سیکورٹی جو ہے، وہ متاثر نہیں ہوگی۔ کیا ہمارے ڈورا سٹیپ ہیں اس پر۔ ایک ایسی سچویشن کریٹ ہورہی ہے کہ جہاں پر آج حملہ کرنے کی تیاریاں ہے، کھلے عام کہا جارہا ہے، اسرائیل کو اکسایا جارہا ہے، اسرائیل کو لیٹیسٹ میزائیل دئے گئے ہیں، امریکہ کی طرف سے۔ کہ جو میزائیل پینیٹریٹ کرسکتے ہیں اندر تک اور جن کا مقصد ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو ڈسٹرائے کرنا ہے۔ پیسہ دیا جارہا ہے۔ ریزیم چینج کی بات ہورہی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہندستان کی پالیسی کیا ہوگی، اگر کل کو یا اگلے دو مہینے کی اندر چھ مہینے کے اندر اسرائیل ایران کے نیوکلیئر سائیٹ کے اوپر اٹیک کردیتا ہے؟ اور وار کی ایک سچویشن بن جاتی ہے۔ ہماری انرجی نیڈس کا کیا ہوگا؟ بھارت کے ڈیولپمینٹ کا کیا ہوگا؟ اس لئے اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آج بھارت کے انلائٹینڈ سیلف کی۔ اس انلائٹینڈ سیلف کا کیا انٹریسٹ

ہے،سر۔ یہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایران سے خطرہ ہے۔ایران بم بنانے کی طرف جاسکتا ہے۔تو جیسا کہ ایک سوال سشما جی نے اٹھایا تھا، میں بھی اٹھانا چاہتا ہوں کہ ایران کو اگر کسی نے دئے اگر نیوکلیئر پلانس دئے کسی نے، تو وہ کون سا دیش تھا؟ کیا وہ پاکستان نہیں تھا؟ کیوں ہمارے پردھان منتری جی اس کا نام لینے کو تیار نہیں ہیں؟ امریکہ کے سامنے نہ لیں، اس پارلیمنٹ کے اندر تو اس نام کو لے لیں۔کیا یہاں پر بھی ڈر ہے! اتنا خوف ہے ہمارے اوپر امریکہ کا کہ ہم پاکستان کا نام نہیں لے سکتے۔ جب کہ ہمیں خطرہ ایران سے نہیں ہے۔ ہم امپورٹر کو تو سزا دینا چاہتے ہیں، جو امپورٹ کر رہا ہے اور جو اس کو بھیج رہا ہے، جو

پلانس دے رہا ہے، جو بیچ رہا ہے اور جو بانٹ رہا ہے، اس کے خلاف ہم ایکشن لینے کو تیار نہیں ہیں؟ ہماری ہمت نہیں ہے کہ بول سکیں۔ کیوں؟ کیوں کہ چچا سیم، انکل سیم مجھ سے ایسا نہیں چاہتے؟ تو سر، وہاں پر بات کوئی ڈیوکلیئر آرمس کی نہیں ہے۔ خود سی آئی اے کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ "Iran is ten years away from any nuclear armament." وہ ابھی دس سال دور ہے ابھی۔ آئی اے ای اے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ابھی اس طرح کی کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ملا ہے کہ وہ نیوکلیئر فیول ارِچ کر رہے ہیں۔آئی اے ای اے نے ایسا کہیں نہیں کہا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم امریکہ کے پیچھے پیچھے تالی بجا رہے ہیں۔

'Like the invasion of Iraq, an (اصل بات یہ ہے، انگلینڈ کا "نیو اسٹیٹ مینٹ" یہ کہتا ہے کہ attack on Iran has a secret agenda that has nothing to do with the Tehran regime's imaginary weapons of mass destruction. that Washington has managed to coerce enough members of the International Atomic Energy Agency' -- نوٹ کیجئے سر، Washington has managed to coerce enough members of the International Atomic Energy Agency -- into participating in a diplomatic charade is no more than reminiscent of the way it intimidated and bribed the "international community" into attacking Iraq in

کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ پانچ ممالک نے جب ووٹ کیا، تو ہم نے بھی ساتھ میں ووٹ کیا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں بھیجنے کے لئے ووٹ دیا؟ کیا سیکورٹی کونسل میں بھیجنے کے لئے ووٹ کیا جائے یا آئی.اے.ای.اے. سیکورٹی کونسل میں بھیجنے کے لئے کیا؟ کیا سیکورٹی کونسل میں بھارت کی ضرورت

ہے، کیا وہاں بھارت کی کوئی شبہ ہے، کیا بھارت کی کوئی پوزیشن ہے؟ ہم وہاں بھیجنا چاہتے ہیں، جہاں ہماری شبہ نہیں ہے، جس کے ہم پرمانٹ ممبر تھے، اور پنجل ممبر تھے، فاؤنڈر ممبر تھے، وہاں سے ہم ایشو کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں ہم اس ایشو کو یہاں رکھنا چاہتے ہیں؟ ہم ایشو کو سیکورٹی کونسل میں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم فائیو پاور کو فالو کر رہے ہیں۔ فائیو پاور آپ کو اپنے دروازے میں گھسنے نہیں دیتں، آپ کو اپنی چوکھٹ کے باہر کھڑا رکھتی ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا ادھیکار ہے، ہم سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں، ہم اتنا بڑا دیش ہیں، تو آپ کو اپنی حیثیت بتادی جاتی ہے۔ بار بار یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم بڑے خوش ہیں اور میڈیا کے ذریعے مڈل کلاس کے اندر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ دیش کا ہت اس میں ہے، ایک بہت بڑی اکانومی پاور ہم بننے والے ہیں، سارے دیش میں دودھ کی ندیاں بہیں گی، ہم گولڈن برڈ بن جائیں گے، دنیا میں سونے کی چڑیا ہوں گے، ہم اکانومک پاور نمبر ایک ہوں گے یا نمبر دو ہوں گے۔ اس میں چین پہلے ہوگا یا ہم پہلے ہوں گے، لیکن امریکہ سے تو پہلے آگے ہم ہوں گے ہی ہوں گے۔

شری اُپ سبھاپتی : آپ کنکلوڈ کریں، پلیز۔

شری شاہد صدیقی : یہ کون پھیلا رہا ہے؟ یہ امریکہ سے پھیلایا جا رہا ہے اور ہم بڑے خوش ہیں کہ بس اتنا سا کرنا ہے کہ امریکہ کے پیچھے چلو، امریکہ سے دوستی کرلو، امریکہ کے ہت کو پورا کردو۔ اسی ہت کو لے کر چلا جا رہا ہے۔

سر، بہت سی باتیں ہیں کہنے کو، مگر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابھی ایک بار میں، دنیش جی اور ہماری کافی ممبرس واشنگٹن گئے تھے۔ ہمارا ایم. پیز. کا ڈیلی گیشن گیا تھا۔ ہم نے کنڈولیزا رائز سے بھی بات کی، اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ سے بات کی اور اپنے پوائنٹ آف ویوز رکھے۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھ کر واشنگٹن سے نیویارک واپس جا رہے تھے، اس سمے میرے ساتھ دنیش تری ویدی جی بھی تھے۔ جو ٹکٹ چیک کرنے والا تھا،

وہ بلیک مین، ہینڈسم، مڈل ایجڈ ممبر تھا، اس نے آکر ہمارا ٹکٹ چیک کیا اور خاموشی سے چلا گیا۔ جب ہم اترنے لگے تو اس نے ہلکے سے آکر پوچھا۔

Are you Members of Parliament from India? I said, "Yes, how do you know?" He said, "The Security Head informed me." I said, "Good." He said, "I am extremely disappointed in India." I was taken aback. I said, "Why are you disappointed in India." He said, "We never expected this from India that India will vote against Iran. We are extremely disappointed." I was shocked.

ایک آدمی ٹکٹ چیکر، جس کا کوئی پالیٹکل کیریئر نہیں، وہ آکر ہم سے یہ کہہ رہا ہے۔

I am extremely disappointed in India. Let me tell you, today the people of Africa, Asia, Latin America and the people of the world are disappointed in our country. There was a time when we led the people of the world. Today we are disappointed; people of India are disappointed because of a policy which is totally not based on any morality, not based on any ideology, not based on any principle and not based on any international law, and still we claim that what we are doing is the enlightened national interest. خدا اس اینلائٹن نیشنل انٹرسٹ سے ہندوستان کو بچا کر رکھے۔ یہ میری دعا ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ووٹ چھ تاریخ کو آپ کریں گے، ہوسکتا ہے کہ اس کو کچھ دن کے لئے ٹال دیا جائے، مگر آپ ووٹ کریں گے، ہوسکتا ہے کہ اس کو کچھ دن کے لئے ٹال دیا جائے، مگر آپ ووٹ کریں گے، تو میری پارٹی اس ووٹ کا پورا ورودھ کرے گی، کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت کے ہت میں نہیں ہے، بھارت کے ہت کو امریکہ کے ہت کے لئے سیکریفائز کیا جارہا ہے، یہ امریکہ کے ہت میں ہے۔ اگر ایسا ہوگا، تو ہم مجبور ہوں گے اس سرکار کے خلاف نو کانفڈینس موشن لانے کے لئے، کیوں کہ یہ سرکار بھارت کے ہت کے خلاف کام کرے گی۔ دھنیواد۔

"ختم شد"

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, India has a glorious tradition of following non-alignment in world affairs. Sir, this principle has been the lifeline of our foreign policy since the days of Pandit Jawaharlal Nehru. Sir, this UPA Government claims that it follows the policies of Pandit Nehru. I am sorry to say that this Government has only been betraying the principles laid down by Pandit Nehru. Sir, no doubt, the world has changed since the days of Nehru, but I am not unaware that we have a uni-polar world today. A uni-polar world is also a dangerous trend and could be the beginning of fascism and nazism. Sir, unbridled uni-polar world would definitely lead to the birth of nazism and fascism. Today, the way the United States of America is treating the rest of the world should make India's foreign policy makers to examine their conscience. Sir, India has been a victim of terrorism for the past 50 years and mostly Pakistan has instigated and funded terrorism. Pakistan has been a client State of the United States of America since its birth. Therefore, this cross-border terrorism would not have taken place without the knowledge of the United States of America. Till September 11, 2001, the USA never bothered about the acts of terrorism sponsored by Pakistan. Washington woke up only after the World Trade Centre was hit on September 11. The point I am trying to drive is that Washington has never been a dependable ally and I can quote any number of instances to prove my contention...*(Interruptions)*.

श्री दिग्विजय सिंह (झारखंड): सर, नोट्स कौन ले रहा है? कोई मंत्री नोट्स तो ले नहीं रहा है।

श्री उपसभापति: दो मंत्री है। दो कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं। ...(व्यवधान)... नोट्स ले रहे हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI DIGVIJAY SINGH: Who is taking notes...*(Interruptions)*. That is what I am asking ...*(Interruptions)*. Will he say that he is taking notes?

श्री उपसभापति: देखिए, बैठिए। मिनिस्टर का उपस्थित होना जरूरी है, वे नोट्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: सर, सदन का समय बर्बाद न किया जाए। ...(व्यवधान)...

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, this shows that the Government is not serious on this issue.

SHRI KALRAJ MISHRA (Uttar Pradesh): Ministers are exchanging notes.

श्री दिग्विजय सिंह: वही तो मैं पूछ रहा हूं कि कौन मिनिस्टर नोट्स ले रहा है? ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: बैठिए, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... नारायण जी, आप बोलिए। ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: सर, यह मज़ाक की बात नहीं है।

श्री उपसभापति: जी।

श्री दिग्विजय सिंह: सर, यह मज़ाक की बात नहीं है, यहां बड़े गंभीर सवाल पर बात हो रही है, लेकिन कोई मिनिस्टर नोट्स ही नहीं ले रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: बैठिए। देखिए, नोट्स लेना या नोट्स कौन लेगा It is not defined...*(Interruptions)*...

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, don't laugh on this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, I am not laughing.

SHRI DIGVIJAY SINGH: I am sorry to say. This is a very serious matter ...*(Interruptions)*.

श्री उपसभापति: आपने जो प्वाइंट उठाया है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि यदि मैं एक डायरेक्शन दे दूं कि आप क्या नोट्स ले रहे हैं They may be so intelligent that they may keep the points in their mind...*(Interruptions)*. Where it is said that I should direct them to take notes....*(Interruptions)*. No, no, it is irrelevant....*(Interruptions)*. Please, there should be no argument on this....*(Interruptions)*. Nothing... प्रभा जी, आप बैठिए। मैं उनको बता रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैं बता रहा हूं न, आप बैठिए। ...(व्यवधान)... It is an issue which is not relevant because nobody can say whether he should take down notes, or what he should do. Nobody can say that.

PROF. P.J. KURIAN (Kerala): Sir, it is a collective responsibility.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Shahid Siddiqui, why all this...*(Interruptions)*... There is no need for any argument here. There is

no rule which says that the Minister should take notes. *(Interruptions)* Please carry on.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, the point I am trying to drive is that Washington has never been a dependable ally. I can quote a number of instances to prove my contention. Sir, what I am trying to emphasize is that in the name of tackling unipolar world...*(Interruptions)*

श्री उपसभापति: मंडल जी, देखिए, आप ख़ामोश हो जाइए। जब आपके कुलीग बात कर रहे हैं, उस समय अगर आप इतनी ऊंची आवाज़ में बात करेंगे तो यह डिस्टर्ब हो जाएंगे।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): सर, इनकी आवाज़ ही बहुत तेज है।

श्री उपसभापति: आवाज तेज है तो दूसरों का भी खयाल रखना चाहिए।

श्री मंगनी लाल मंडल (बिहार): वह क्या है कि ...(व्यवधान) *Please don't disturb. (Interruptions)* Pleased don't disturb.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, in the name of tackling the unipolar world, we should not be putting all our eggs in Washington's basket. This is what is happening now. Sir, the Prime Minister, before he went to Washington in July, 2005, made a statement that nobody questioned. Nobody questioned his credentials at that point of time. Talking to media persons, before his visit to Washington, he said, "India cannot be a puppet of any country". I do not know why the Prime Minister chose to make such a statement at that point of time.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, he is raising the issue of a statement about which...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, please let the debate go on. Otherwise, the Member will say that because there was disturbance, give me additional time. They will ask for it. Are you going to give time?

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, during his visit to Washington when Americans promised the moon, nuclear fuel, the Prime Minister made another statement. The statement was revealing in the sense that the policy makers even at that point of time have decided to dump Iran. The Prime Minister said, "I do not know whether the Indo-Iran Gas Pipeline is

feasible". The statement was made even before the ink had dried on the Indo-US Nuclear Pact. Sir, I am told that the US Ambassador in India, Mr. Mulford, is a close friend of President Bush. By his behaviour, we get an impression that Mr. Mulford is the Prime Minister of India. Whatever remarks Mr. Mulford makes, however damaging they are, the Prime Minister is defending him. Mr. Mulford wrote a letter to the Chief Minister of West Bengal....*(Interruptions)*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. There was a reply..*(Interruptions)* Recently, we had ...*(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, he is again trying ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Mr. Narayanasamy. Please sit down. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, kindly correct it. Sir, the other day, the Prime Minister himself has clarified it. *(Interruptions)*

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, he is interfering ...*(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Why is he questioning the statement of the Prime Minister?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, Mr. Narayanasamy. *(Interruptions)* You said that the Prime Minister is defending him. There is nothing on record that the Prime Minister defended him. *(Interruptions)*

SHRI BALBIR K. PUNJ (Uttar Pradesh): Sir, in the time allotted to every speaker, please add 50 per cent for Mr. Narayanasamy. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But he has no time. That is the problem.

SHRI P.G. NARAYANAN: Sir, it is not good on the part of ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, when he is speaking on the subject, it is alright. But when he is telling something which is beyond the ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Narayanasamy, the Chair will take care of what they have to say. If I need your assistance, I will ask ...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I will bring it to the notice of the ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If I will need your assistance, I will take it. Right now, I don't need your assistance.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, he is taking advantage of the absence of ...*(Interruptions)*...

SHRI P.G. NARAYANAN: There has been a widespread demand that Mr. Mulford should be recalled. Our Chief Minister has also made such statement. But, I know that the Government of India will not act in this matter. I am surprised that we voted twice against Iran at the International Atomic Energy Agency meeting at Vienna.

Sir, what is disturbing me and my party is, there is an intensive competition between India and Pakistan on who will be a reliable client state of the United States of America. India should have its own identity. We are a 3,000 years old civilization. In the matter of playing second fiddle to America on all world issues, the foundation was laid by the former Prime Minister Mr. Vajpayee and now the present Prime Minister is continuing it. So far as the Iran nuclear issue is concerned, I oppose the stand taken by this Government. Thank you, Sir.

SHRI K. RAMA MOHANA RAO (Andhra Pradesh): Thank you, Sir, for permitting me to speak on this delicate, sensitive and complicated issue of Iran's nuclear programme concerning not only India, but the entire world. This is the testing time for India and it is at the crossroads whether to follow the path of Non-Aligned Movement and independent policy that we have been pursuing since our Independence, or, succumb to the pressure of a few developed countries. Shri Raashid Alvi, while seconding the Motion of Thanks to the President's Address said that this is an opportunity for India to be with the USA to become strong and whatever policy we pursue should be in compliance with it. I don't know whether it is the stand of the UPA Government. If it is so, then, we oppose this lock, stock and barrel. When, I say this, I do not mean that we are

opposed to the US. We are not opposed to the US as such; we are only opposing the Bush Administration. It is relevant to draw the attention of the hon. Members to the stand the US had taken during our 1971 conflict against Pakistan. The US had moved its fleet to wage a war against the US.

Sir, the first point I wish to make is: Why are we singling out Iran? Why is the IAEA focusing on Iran alone? The hon. Prime Minister has said in his statement, "It is a matter of concern for the US as tensions in this region—where our vital political, economic and security interests are involved—affect the US." Do we sincerely feel that Iran is the only potent threat to India? Don't this region have any threat from the other Middle East countries? We are already surrounded by three nuclear powers. What efforts India, Europe, the USA and the IAEA have made to make this region a nuclear-free region? So, it is, to some extent, I would say, an exaggeration of the situation to say that we have threat only from Iran.

The hon. Prime Minister again said, in his statement, that important NAM and developing countries such as Argentina, Brazil, Egypt, Ghana, Singapore, Yemen and Sri Lanka are also supporting this. I am aghast to learn that hon. Prime Minister compared India with these countries? Are you comparing India with Ghana? Are you comparing India with Egupt, Yemen and Sri Lanka? If these are the countries with whom we have to compare ourselves, if these are the countries whose line we have to toe, then I am sorry I am not prepared to leave this to the prudence of this Government. Sir, we are not a spineless country. We are not a Banana Republic. Now, India has reached a stage to dictate terms to any developed country in the world. Those countries might have succumbed to the pressure of the USA. But, how a strong country like India, whose foreign policy is virtually based on Non-Aligned Movement, that has been adopted by Pandit Jawaharlal Nehru, along with two other great leaders of the world, Marshall Tito of Yogoslavia and Mr. G.A. Nasser of Egypt, as its basis, can succumb to such pressure? I am not against the US as such. I am only against the way this issue is being handled and the way they are pursuing the 'policy of authority' on others. After the March vote, it is inevitable that the the US will use its force against Iran; the way it did in the case of Iraq. And, ultimately, the Security Council will remain a mute spectator. Sir, a Report appeared in *The Sunday Telegraph.*

The Report says that the U.S. is drawing up plans for bombing

raids on Iran. It has also said that the planning went beyond contingency assessment. Sir, the U.S. Central Command and Strategic Command planners are identifying the targets in Iran. So, if you look at this closely, is it not a sheer violation of entering into the internal affairs of another soverign country? And, after some time, if the U.S. asks India or its troops, what would be the stand of India? If we refuse, the U.S. will bring the nuclear cooperation issue on the surface and force us to send our troops. So, where are you taking our Foreign Policy? I strongly feel that it is no longer independent. To maintain good relations with one nation cannot be at the cost of good ties with another. *(Time-bell)*

Sir, the other point I wish to make is this. Sir, America is shouting from the rooftop that Iran is indulging in making nuclear weapons, and France and Germany have become the staunch supporters of the U.S. Now, they are saying that it should discard itself from this whole activity. But it is surprising to know that when Iran started its nuclear programme in 70s, there were the U.S.A., France, and Germany which supported Iran. Now, it is surprising how these countries are opposing Iran's nuclear energy programme. They may say that Iran is using this for clandestine ends. But how can they say so without any substantive evidence? Sir, America itself has helped Iran in setting up Tehran Nuclear Research Centre. Now, this Centre is also producing nuclear energy. There is one more reactor in Bushahar which Iran got from Germany. Of course, later on, with the help of Russia, it has completed the project. It is also known to the entire world that there was an agreement between Iran and France to set up Dar-Khovin Nuclear Reactor. When these many reactors were established with the help of these very countries, how are they now saying that Iran is using these plants for producing atomic bomb without any substantive or concrete evidence? Though Iran was not in need to produce nuclear energy in 70s, since its population at that time was less and the energy consumption was also low and, moreover, the oil production was more, it had started producing nuclear energy only by looking at the energy requirements for its future. But, now, the situation has changed. (*Time-bell*) The population of Iran would be 10 crores by 2025, and its energy requirements have already been increased by four times in the last two decades.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude.

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Sir, I will take only two more

minutes. So, to meet all these requirements, Iran definitely needs to produce nuclear energy since fossil fuels are fast depleting. When I say this, I did not mean that Iran be given a free hand. If the international community or the IAEA substantiate that Iran got clandestine devices through which nuclear technology and material have been transferred to Iran, then, in the interest of our country, we should definitely take appropriate action. Iran is a signatory to the NPT and there is also an obligation on Iran to fulfil the international commitments. If IAEA really found sufficient evidence that Iran was proliferating Uranium for other purposes, then, the U.N. is the authority to take appropriate action, but not at the behest of the U.S.A.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude.

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: The next point I would like to know from the hon. Prime Minister is this. What are the complications or implications that India is likely to face if she remains absent from the voting on 2nd March? Becasue the countries such as Cuba, Venezuela and Syria have voted against the Resolution in the second round and even Non-Aligned countries like South-Africa, Indonesia, etc., have abstained. India can also abstain from final voting to maintain a balance in relations with Iran, and to keep our Foreign Policy independent. At the same time, we should also strengthen our friendly relations with the neighbouring countries, so that we can reduce spending on Defence and the money so saved can be spent on backward area development.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How many points are there?

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: The final point I wish to make is that India, particularly Shri Mani Shankar Aiyar, pursued vigorously with Iran, Pakistan and other concerned agencies to start the dream pipeline project of Iran-Pakistan-India. If India votes in favour of the Resolution in March, what would happen to this project which, I am sure, would meet the meximum energy requirements of our country? Not only this, we also have other minor projects in Iran. What will happen to those projects?

So, I would only urge the hon. Prime Minister to wait for the outcome of Iran considering the Russian proposal and probably, this solution may be in the best interests of our country without antagonising Iran or other countries opposing unipolar policy of dictating terms to other sovereign nations by the U.S. Thank you very much, Sir.

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I listened with great attention my friend Kapil's speech. The best thing that he said at the end was that this is not a matter in which we can be guided either by emotion or by indignation. This is an extremely serious matter. It is not a communal issue. It is not even an issue of the moment; it is an issue, a perennial issue, of our long-term survival in the comity of nations.

Sir, I regret that I have today to oppose my friends in the Left. They will acknowledge one thing that when I was young, Sir, I was an unmitigated critic of communism. But since then, they have won me over and I am almost 95 per cent with them on the issues which practically cover every important aspect of political life and social life. I am one with them. I am one with them on the issue of secularism; I am one with them on the issue of corruption which has become a tremendous disease in this country; I am one with them on the most callous problem that faces us, the problem of poverty; and, Sir, more than anyting else, I am with them on their core issue about fair distribution of wealth. As I said, Sir, today, my friends will concede to me that I am almost their admirer and their supporter. I am not formally a Member of their party, but, Sir, I have two issues on which I still have some differences with them. I hope during the course of our intimacy which continues to grow, we will be able to resolve even these two differences — one is an aspect of foreign policy and the other is, techniques of production of wealth. They have no experience of production of wealth. They have great experience of distribution of wealth. But by distribution of wealth, they have always meant distribution of poverty. Sir, as I said, this is an issue of great importance. We are being criticised by the manner in which we have cast our vote in February last. Sir, let us. first put the vote in its proper

4.00 P.M.

perspective. What have we done against Iran that so much of indignation is being invoked? We have not voted for the destruction of Iran. We have not voted that Iran should be out-lodged from the United Nations. We have not voted for sanctions being imposed on Iran. What is it that we have done against the interests of Iran that today we are being told that if this does not happen, if the Government does not reverse its vote which it has cast in February, some heavens are going to fall and so many parties are going to sort of withdraw their support, and so on and so forth. Sir, first of all, all that has been decided on the 5th of February

when India voted, it was decided that the Security Council, under the Charter of which we are members and to which we are signatories — the Security Council is the main body charged with the maintenance of world peace and security — that the Security Council must be told of two things. Firstly, Iran is in breach of its obligations under the Non-Proliferation Treaty and secondly, that it has undoubtedly ambitions of manufacturing a nuclear bomb. That also, we suspect that it has not given up that ambition and it entertains these ambitions. Sir, it is this which was only to be reported to the Security Council... so that the Security Council, in its full Session, will ultimately apply its mind and decide what should be done or what should not be done, still leaving room for negotiations, for a consensus to be arrived at. Sir, here, I regret to say that my friend, Shrimati Sushma Swaraj, should have levelled an insinuation, and almost an allegation that this Government and India have lost its self-respect. Sir, I want to know that when we cast this vote, we cast this vote in the company of all the five permanent members of the Security Council, including Russia and China. Is it being suggested by any person in this country that Russia and China were pressurized by the Americans to vote in a particular manner? We voted because we thought that this was in the interest of world peace that this report must go to the Security Council so that the Security Council apply its mind and the Security Council should not, thereafter, say that, yes, you had suspicions about the bomb, you had suspicions about the breach of obligation, but you never even reported back to us. So, how can you blame us? We have only shifted the responsibility to the Security Council. The Security Council will ultimately decide this particular matter. A question has been asked: Why have you singled out Iran? Nobody has singled out Iran. From amongst whom has Iran been singled out?

Sir, I want to talk now, unfortunately, about the qualifications of Iran for having attracted this vote and attracted this course of conduct from India. First of all, I am a lover of Iran. I associated myself with Iran as a student of literature with Omar Khayyam, with peace and by the side of me a jug of wine. Now, what has it become? It is now a country which is threatening the world peace. Twice, the duly elected President of Iran has gone on the world stage and said, first of all, Israel must be wiped off from the map of the world. He then made a second statement that it should be shifted to Alaska. Sir, whether you like Israel or not, Israel is a member of the United Nations; we are a Member of the United Nations, and we shall not stand for any country of the world, however big and

powerful it is, saying that another member should be wiped off from the map of the world. If tomorrow, Iran were to announce that Pakistan will be wiped off from the map of the world, I will go to Pakistan though my energy at this stage is not worth anything, I will give my little life for the defence of Pakistan if Iran were to say that Pakistan is going to be wiped off from the map of the world. I will do it for Palestine, if tomorrow Israel were to say that they will wipe off Palestine from the map of the world. I will go and fight on behalf of the Palestinians. But, Sir, we cannot, in a civilised society, behave like this, and I make good to say that India's conscience, India's self-respect, India's self-interest, India's national interest, all unanimously require that we must stand up and be counted for the first time. I have been a student of International Law; I have been a critic of non-aligned doctrine. But, for the first time, in the history of India's international conduct and relations, we have acted in a non-aligned way because now, we are both with the Americans and the Russians, in addition to the Chinese, all speaking with the same voice, and this is the first non-aligned action which India has now taken in the comity of nations.

Sir, the first point is, here is a country whose President has said that we are going to wipe off another member of the United Nations from the map of the world. The second point is, it is obviously, manifestly and undeniably a breach of its obligation under the Non-Proliferation Treaty. Nobody denies it. That is an acknowledged position. If you deny now and save Shrimati Sushma Swaraj, who said that Pakistan has supplied them the nuclear weapons and all that, I would say that I am not an advocate for Pakistan. But I am a great advocate of Indo-Pak friendship as well. I want to be a friend with Pakistan. But that does not mean that we have condoned the action of Pakistan in having given these atomic and nuclear weapons, and at least, the means of producing those nuclear weapons to Iran, and if Pakistan has done it, as was stated by Shrimati Sushma Swaraj, why did you not denounce Pakistan?

Sir, this is not the way in which the world diplomacy is carried on, as she thinks. Every country has to be dealt with in its own way, in its own context and in its own circumstances. We are carrying on now a peace process with Pakistan. Therefore, we go and tell President Musharraf, when we meet in private, "what is this, Mr. Musharraf? What is this Mr. President? Why are you distributing all these weapons of mass destructions throughout the world? Don't do it". They have never talked

to President Musharraf. They don't even know that President Musharraf is sorry for what has happened in this country and in his country. But what can he do? He is also waiting for something to be given to him by us so that he can sell it to his own people. The man has moved away 180 degrees. He was the creator of Al Qaeda; he was the creator of Taliban. He has moved away 180 degrees and is now fighting the very Frankenstein which he has created. Maybe, his fight is somewhat half-hearted; maybe, he is not doing it with full vigour. But he is still trying to do it and hats off whatever the way. We will deal with Pakistan when the time comes.

The second circumstance against Iran is this. Three years ago Iran behaved in a reasonable manner. It gave an undertaking that it would not resume uranium enrichment. Then it gave notice, "We are now going back on the promise which we made and we will start uranium enrichment". When they did it, their friends, the Russians, who were very anxious to drive a wedge between America and Iran, said, "You come and enrich uranium on our soil; we will oversee it and we will certify that you are doing it for peaceful purposes". They rejected the offer which came from their friends, the Russians. When the Russians and the Chinese decided that they should go to the Security Council and report back, India joined in that vote. Nobody can say that it has been done under pressure. It is not pressure. I have always said that the one great maxim of international life is "या तो शेर बनो या शेर के बगल में बैठो"।

Today, the world acknowledges that America is the single unit, the only power, which has tremendous military and financial power at its disposal. What is wrong in entering into a partnership with that most powerful country of the world which was arrayed against us at one time? When Pakistan struck friendship with America and the Americans and the Pakistanis were acting against our interests, I had not seen that much howl against the friendship between America and Pakistan as I am seeing now, when we are trying to sort out the spoiled relationship with Iran. At that time, in 1974, and particularly in 1998, when we made our own bomb, what happened? We became international barriers. We became the victims of a conspiracy of the whole world of nuclear power suppliers and our industry is suffering. We require electrical energy which can come only from nuclear sources and our energy needs are so much that our industry and prosperity can never go ahead unless we acquire nuclear power.

Sir, look at President Bush who is being abused. The world of diplomacy is a very sophisticated and gentlemanly world where even if we have to abuse, we have to abuse with grace, with such a finesse. The language employed is the language of polite diplomacy in which we don't call a spade a spade. What is said today? Bush is a murderer; he is a killer; this man is coming. This harsh language of diplomacy will not ever pay us any dividends. It is in our interest that the two world democracies must come together and face the forces of dictatorship and face the forces which are fighting against secularism. I can't even claim that Iran is democracy. Nobody can claim that Iran is a great secular power. Let us not forget that Iran is the creator of Hizbullah Movement. The whole Shia militancy has grown, financed and nurtured by Iran. I don't know how many Members of this House have read Mr. Lapierre's book "The Fifth Horseman", who was the co-author of "Freedom at Midnight" with another gentleman.

Sir, read that book and you will see what kind of chaos, consternation and dislocation of every kind of social life can be created by one nuclear bomb coming in the hands of the terrorist. Sir, read that book and you would realise what is happening. Today a country which nurtures Hizbullah; the chief terrorist movement of the world is located in Iran and I am surprised that people are here who are showing so much concern and sympathy with Iran. If one Hizbullah terrorist takes one nuclear bomb in his hand, the whole world can be held to ransom. Be sure, Sir, we are going to be the victims. It is our security which is going to be at stake. I am surprised that today the BJP is beginning to talk in that vein and my friends, the Leftists, should realise that when you are joining hands with them, you must be on the wrong side. Sir, I am very happy that you have given me this opportunity. I wish to end up with Gandhiji. Gandhiji had said that when India becomes independent, we shall have no military power, but we shall have moral power and with our moral power we shall stand up and tell the whole world that we mean to be the conscience of humanity and we will speak up and speak up the truth to everybody. It was Gandhiji who said this. Sir, the Constitution-makers framed the foreign policy. You talk of national interest. Shri Kapil Sibal talked about it. But please understand that Gandhiji explained to posterity where India's national interest or enlightened self-interest will lie. That is how we came to enact article 51 in our Constitution. Article 51 says that India shall be

working for international law, for international organisation and for settlement of world peace and for settlement of disputes through arbitration. I want to resolve the problem with China. I want to resolve the problem with Pakistan. Make a little give and take. Solve those problems. Throw away and dump your nuclear weapons. Make it nuclear free. Save that money for the poor people of this country. Then my friends will bless me that I have done something for the interest of those whose interests you hold so dear. I have no doubt, honestly, but your methods and techniques are mistaken. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Prof. P.J. Kurian. Prof. Kurian, just a minute. The Leader of the Opposition wants to say something. (*Interruptions*).

PROF. P.J. KURIAN: Sir, if he wants to intervene, I am ready to yield.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He just wants to intervene.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI JASWANT SINGH): Sir, neither do I want to break the queue nor take anyone else's assigned place or time. I have only a few submissions that I want to make. I heard my senior and my good friend, Shri Ram Jethmalani's impassioned intervention with great interest. He talked, far and wide, about Indo-Pak relations and Indo-US relations. This is a complex mix that we are discussing today under the rubric of the IAEA vote. I have, Sir, found it an enlightened debate and I must say that all participants and parties spoke with such an abundance of enlightened self-interest and party interest, that I think, it might be useful if we did not attach this prefix of national interest as this lends itself to rather subjective interpretations for enlightenment, for what can be enlightened under one circumstance, need not be so under another. I want to come to some specific points.

There were some references made about consensus, that consensus is important on this matter. I don't dispute that at all. But I really wish that the Government does recognise that consensus is not possible if decisions are mid-night decisions, and I remind the hon. Members of the manner in which the first decision was taken. Also that consensus is not possible when the Cabinet itself was not consulted before such a decision is taken. And, consensus is really very difficult to achieve with those of us who are not privy to this decision-making. When

even the allies are not consulted, then certainly you will not have the consensus. Despite that, I do wish to say that consensus would be a good thing, but consensus can take place only if you consult with us.

Sir, I beg to be heard on these two issues, both on the IAEA vote and the other on which the hon. Prime Minister will speak to us at 5 o'clock; I wish there are clarifications again because there seems to be now establishing a new pattern that statements are made in this House and we are denied the opportunity to seek clarifications. My good friend, hon. Sitaram Yechuryji, — he is not here — wanted to quote something which I had said something back. I really wish he had quoted it because I do not recollect what I had said. There are two things; whatever is said while discharging a responsibility, particularly in this field, समय, पात्र और काल को देख कर कहते हैं। In fact, personally, I would want, Sir, that he upholds the view which he held at morning. It is not necessary that the views that were held or expressed in a certain circumstance, in 2000, at a certain locale, hold good now; the circumstances have since altered.

The hon. and distinguished Member of the Union Cabinet spoke on reciprocity and gave many examples. He said that the absence of reciprocity in Iran's vote, therefore, should really not matter. I don't think reciprocity is always a factor. But reciprocity is a factor but to be advanced as a proposition only in the case of Iran then it must be with the United States of America too. If reciprocity has to be the criterion by which you are going, हम इन गलियों में बहुत घूमे हुए हैं, इसलिए हमें जो कुछ अर्ज करना है, उसी की बेसिस पर करना है। Then apply it uniformly.

The other argument that was given was about energy. It is that because we need energy, therefore we need to do this. Yes; of course, we need energy. I don't think anybody disputes that and says that we don't need energy. In fact, it was late Mrs. Gandhi who had announced — I forget the year exactly — that our aim is to produce 10,000 MW by 2000 A.D. This was announced at least 15-18 years before the programme was launched. You know where we are now. I think we produce on an average 2300 MW; in a good year, we might produce 2300 to 2600 MW. There is a great shortage; I agree. But then that is a different debate as to what we should have done, etc. This is a requirement, but if after all this, the contribution of nuclear energy to the total energy requirements of India, as my good friend, Shri Sitaram Yechury, has said, is going to be

only 3 per cent, then, please don't beg everything on to the energy security argument, because the energy security aspect covers other aspects of energy, and it would be my recommendation to the Government not to base its argument on this factor of energy security alone, which, as it appears, the Prime Minister has been strongly advocating uptill now.

There was also, Sir, this aspect of the hon. Minister who intervened on behalf of the Government. He spoke of the IAEA Report of 2003. He also said that it is possible that Russia I wish to correct some of the mis-impressions that the hon. Minister's intervention might create. First, he said that it is well enough known to everyone that Iran had a certain programme, it was headed in a certain direction, and that programme is not of 2003 vintage, it actually, goes back almost two decades. I would not go into the exact number of years, but it does, really, go back.

SHRI KAPIL SIBAL: It was started in 1991 ...(*Interruptions*)... To be exact, 1987 to ...(*Interruptions*)... Sixteen years; 1987 to 2003 ...(*Interruptions*)...

SHRI JASWANT SINGH: I know; I know. But, it really started before 1991, you don't suddenly start a nuclear programme. But, however, Sir, on that detail, I will be happy to be better educated about. But, the fact that remains is, Sir, that this aspect of Iran's nuclear programme and aspiration was well enough known. What has transformed the situation now is a different attitude and approach, and different security pronouncements of the United States of America. Now, there is need, Sir, for us to recognise, as my friend and senior colleaugue who is far more eloquent than I possibly can be, has said about Indo-US relations, or about Indo-Pakistan relations, etc. Yes, of course, who says that India and the United States should not have the best possible of relations? But, there has to be recognition, Sir, that the best possible relation has to be structured on the foundation of a congruity of national interests. That, I am sure, even the Government cannot or will not dispute.

Sir, may I submit for the Government's consideration that because of the inter-linkages, please recognise that this vote of the IAEA and the Agreement of the 18th July with the United States of America have a direct nexus with the whole question of the fissile material, which is not even a treaty, the FMCT, which is still under consideration in the Conference on Disarmament in Geneva? I think, it is also necessary for

us to recognise that when the IAEA submitted its Report, did it say what Sushmaji has said about cooperation by Iran. The violation they found was principally on two grounds. On one of the centrifuge parts, traces of enriched uranium were found on a particular blade. The origin of this centrifuge part, or, the blade of it was traced back to Pakistan. Secondly, Sir, some drawings were found; it, really, get traced back to the People's Republic of China; obstetrical objects which can only really be for the production of a nucler device. Now, on this basis, the United States of America has structured its whole approach. You could reason this; you could say this is a valid enough rationale. It is reminiscent somewhere, or, it has echoes of the approach that was adopted pre-Iraq actions. Somebody had asked me, Sir, then, do you think that Iraq has Weapons of Mass Destruction, before the military action had started? And, I had said, "it is really rather like a *sura* painting, *sura* painted in dots".

So, the dots created an illusion of whole picture. In Iraq's case, there were dots but they did not complete a picture. In this case, I am afraid, even that is difficult to accept. The direct linkage to us and our national interest is not, therefore, energy; it becomes the Fissile Material Control Treaty. If the alternative route to non-proliferation is now going to be a curbing of a fissile material, it is what is being done in this case, that will an apply to India, which I do not think an exception can be made for long in this regard. I have submitted this very viewpoint to the Government, Sir, at appropriate time in the best possible fashion that I could because I had an opportunity. I did not have any opportunity ...(*Interruptions*)... I will complete, Sir. I am grateful to you that you gave me time ...(*Interruptions*)... Just remember one more thing that so far as the history of USA-Iran relation goes, Sir, it goes back to Masadaq's removal from office. That goes really way back. We have perhaps forgotten that Masadaq was the first elected democratic leader of Iran who gave up his life to protect Iran's oil interests. That was democracy. That was democracy in action. In Iran what happened?

SHRI K. NATWAR SINGH: In 1952.

SHRI JASWANT SINGH: Yes, 1952. I was still at school. But I know that hon. Natwar Singhji was already knocking at doors of Foreign Service. We have to see historic continuity because somewhere in some fashion the national interest of that particular country will repeat itself. Now if the national interest of the United States of America required that Masadaq

be removed, that Anglo Iranian oil company, then, really a private company owned by the Britishers, I do not think the Americans were really even there to force their way in. Please remember that this whole business could well come back to us in this indirect route. We might not end up by getting too much enriched uranium. But we could end up by losing the options that we have of FMCT, which directly impinges on our minimum credible guarantee plus. It is very important, Sir, whether '98 convinced everybody or not convinced everybody, but '98 did for India without any doubt, was to get for India the strategic sovereignty and the strategic space that India needed to take decision on its own without being pushed or hassled or bludgeoned into a particular position. If reciprocity is the theme, even the agreement that was signed on 18th July, what was spoken about was simultaneity, reciprocity. Now we have phrases like "India will be doing this first, then we will do it. India will do this thing in perpetuity." It is reflected; we are not chronically either anti-Government or anti-US. Perhaps we are not as enlightened as the ruling establishment is, somewhere that enlightenment might have struck us occasionally, that is why I appeal to you, do not hassle the rest of the country in this direction because the Government is being hassled by the United States of America.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two more speakers. ...(*Interruptions*)... Your name is there, but we have to conclude at five. You can speak on some other occasion. ...(*Interruptions*)... Your name is there. ...(*Interruptions*)... I called your name, but you were not here. ...(*Interruptions*)... Prof. Kurian.

PROF. P.J. KURIAN. Sir, I have great respect for the Leader of the Opposition and when you asked me to yield, I yielded willingly thingking that he will take only one or two minutes. But he made a full-fledged speech. So, I would also like to take one or two points from his speech. First of all, he was talking about the nuclear energy.

It is for the purpose of nuclear energy that we have done this. That is nobody's case. Hon. Minister, Shri Kapil Sibal has well explained it. We have taken this position in the best national interest. I think on two points, there is no disagreement here. Firstly, national interest and secondly, nobody is here for nuclear proliferation. Nobody is here. Nobody here wants our neighbour, our extended neighbour to have a nuclear bomb. On that there is full agreement. To achieve that, what is the best decision? Sir, it is in Iran's interest to violate, according to them, to violate

the NPT, which they themselves have signed. We have not signed. And a pertinent question was asked by the hon. Minister whether we should support a country violating an agreement, which they have willingly signed. That is an unlawful thing. It is against law. They have signed an agreement. Should we say that is right? Maybe it is in Iran's interest. It is in our interest. Secondly, in all evidences, which have been well explained here, all evidences point to the fact that Iran is going to develop a nuclear bomb. Further more, it has been quoted from IAEA report that the sensitive technology required for that—which the hon. Leader of the Opposition himself explained—has been imported clandestinely from a country which is our neighbour. That country is our neighbour and hon. Member, Sushma Swarajji says why not that country be named in the statement. Ask Sushma Swarajji, everybody knows which is that country. Everbody knows that it is not Sri Lanka. It is not Myanmar. Everybody knows that it is not Bangladesh.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: If everybody knows then why this hesitation?

PROF. P.J. KURIAN: No, I am not yielding. I am not yielding. I heard you saying, why not ...(*Interruptions*)... I am not yielding.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You speak. You go ahead. Whatever you are saying it is going on record.

PROF. P.J. KURIAN: Sir, I heard Sushmaji saying that it is Pakistan and why that name of that country was specifically not mentioned. I am only saying that everybody knows that. My point is that this clandestinely sensitive technology was made available to Iran by this country which is our neighbour. Therefore, is it in our interest to have a nuclear weapon possessed by that country or a friend of that country and eventually as has been said here if that bomb goes into the hands of terrorist, what will be our position? In the world, more than America, we are the first victims of terrorism and when you were in Government this Parliament was also attacked. So, I say, I am not alleging anything but, yet, I am saying a patriotic mind cannot consider anything else. It is not a question of emotion. There is no question of dogma here. There is no question of obsession. I think the Communists are my good friends. In Kerala, we are fighting but here we are good friends. I agree with many of their proposals. I agree with many of their views. For example, when they say there should not be FDI in consumerism I agree with them. They are dogmatic. They are not pragmatic. They are obsessed with anti-

Americanism. Therefore, simply because of the fact that we voted in our interest which we found is in our best interest and because that coincided with American interest they say that we voted with them.

Why don't you say that they voted with us?...(*Time-bell*)... The BJP has a problem of American obsessinism. They are obsessed with America. It is because when they were in power, they were hobnobbing with America. Madam Sushmaji, it is we—Indira Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Rajiv Gandhi—stood for Non-Alignment and stood against the American imperialism. When you came to power, you hobnobbed with America, not we. Sir, you are blaming the hon. Prime Minister and also spoke about the Iran pipeline project. She made a particular statement on the Iran Pipeline project. Sir, it is the same hon. Prime Minister who said on the American soil that 'Iraq invasion is on.' Did any head of the nation say so? Yet, you don't accept that. Your problem is that you don't see that. There is a saying in Malayalam. It means that even from a cow with full of milk, mosquito can only suck blood. That is your problem. I would like to submit that our hon. Prime Minister and this Government have taken this decision in the best interest of the nation. The best example for our standing is that our hon. Prime Minister on American soil criticised the American action in Iraq.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Kurian, please conclude. There are three more speakers and we have to finish the debate by 5 o'clock.

PROF. P.J. KURIAN: Sir, the hon. Leader of the Opposition has taken my time. So you have to give me more time.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I Know, I know. But, sometimes, we have to sacrifice some time.

PROF. P.J. KURIAN: Now, Sir, I say what is friendship. Friendship with Iran does not mean that you agree with everything it says. They have a perception. We may have another perception. We once voted against Iran do not mean that we have lost our friendship. Our friendship remains.

What is Non-Alignment? Again, it is something in our national interest, Majority of the Non-Aligned nations—Russia, China, Brazil, Egypt, Indonesia—voted along with us. That means we are with the majority of the Non-Aligned nations? How can anybody say that we are not with Non-Aligned Nations? How can the left or you say that we have violated the NAM Principle? We stick to the NAM Principles. Sir, it was asked here as to what was Rajiv Gandhi's Plan of Disarmament. Shri Rajiv

Gandhi announced that Plan in the UN whereby he wanted that by 2010 the world should be devoid of all nuclear weapons. We are sorry, he is not here to ensure that or to implement that plan. But the Government sticks to that plan. We are for disarmament and we are for removing all nuclear weapons. But, we have to be pragmatic.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude.

PROF. P.J. KURIAN: We cannot just close our eyes when our neighbours are developing nuclear bombs. And, we cannot ensure that those bombs are not made available to our enemies. Therefore, in the best interest of the nation, in the best interest of the people of this country and in the best interest of all of us, the Government have taken this decision. And, this Government deserves support for this. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members there are three more Members to speak—Mr. Digvijay Singh, Mr. Manoj Bhattacharya and Mr. Chandan Mitra. We are left with only twenty minutes. I request the Members...

डा॰ कुमकुम राय (बिहार): और हमारी पार्टी का?

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, मेरा भी नाम था। मुझे कहा गया था कि 7 नम्बर पर मेरा नाम है, मैं खिसकते-खिसकते बाहर चला गया!

श्री उपसभापति: आप अंदर ही हैं।

श्री मंगनी लाल मंडल: हर बार ऐसा होता है मेरे साथ।

श्री उपसभापति: आप अंदर ही हैं। Please take five minutes each and whatever points you want to make, you make within those five minutes. Mr. Digvijay Singh.

श्री दिग्विजय सिंह: सर, उस समय भी हमसे कहा गया था कि आप दोनों विषयों को क्लब करके बोलिएगा, मैं पांच मिनट में तो अपनी बात नहीं कह सकता। मैं बैठना पसंद करूंगा। मैं नहीं बोलता, दूसरे लोग बोल लें।

श्री उपसभापति: आप बोलिए।

श्री दिग्विजय सिंह: माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस बहस की शुरुआत सुषमा जी ने जिस ढंग से की थी और जिस समय श्री सीताराम येचुरी जी बोल रहे थे, तब नटवर सिंह जी ने उनका थोड़ा सा करेक्शन किया था कि वह 1946 नहीं 1947 था। मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं बोल रहा हूं तब नटवर सिंह जी, आप यहां पर मौजूद हैं। मैं आपको 1946 से भी थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, जब हम गुलाम थे। जब हमने आपने आज़ाद हिन्दुस्तान के नक्शे दुनिया को बताने की कोशिश की थी

कि जब भारत आज़ाद होगा तो दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करेगा।

यह बात 1927 की है, जब महात्मा गांधी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू को ब्रुसेल्स में लीग एगेंस्ट इम्पीरियलिज्म में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था और उस लीग एगेंस्ट इम्पीरियलिज्म में हमने दुनिया को बताया था कि अगर भारत आजाद होगा तो हम अकेले अपने लिए ही नहीं लड़ेंगे, बल्कि दुनिया के उन तमाम गुलाम देशों के लिए लड़ेंगे, जो आज गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और आखिरी सीमा तक लड़ेंगे। हमने इस बात को साबित भी किया। दक्षिण अफ्रीका के सवाल पर हम दुनिया में अकेले खड़े थे, लेकिन हमने किसी के भी सामने समझौता नहीं किया। भारत अकेला ऐसा देश था, जिसने कहा कि हम तब तक दक्षिण अफ्रीका से कोई संबंध नहीं रखेंगे, जब तक वहां पर रंग-भेद की नीति समाप्त न हो जाए और श्री नेल्सन मंडेला जेल से बाहर न आ जाएं।

उपसभापति महोदय, मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई में देश और दुनिया को और साथ-साथ इस देश के लोगों को भी इस बात का दीवाना बनाया था कि हम आज़ादी के बाद क्या करने वाले हैं। आज 60 साल की आजादी के बाद अगर हम फिर से इसी सवाल पर खड़े हैं तो मैं नटवर सिंह जी के सामने एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा।

1991 में जब मैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में ईरान, तेहरान गया हुआ था। यह घटना तब की है, जब ईराक पर फिर से युद्ध हो रहा था और नैम (NAM) की तरफ से चार सदस्यीय देशों—भारत, क्यूबा, ईरान और यूगोस्लाविया की एक समिति बनाई गई थी, उस समय यूगोस्लाविया नैम का चेयरमैन था। मुझे प्रसन्नता है कि उस समय श्री राजीव गांधी एक गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल को लेकर तेहरान पहुंचे थे। उस सदस्य मंडल में आठ सदस्य थे और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी भी उसमें मौजूद थीं। मैं इसे इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि, नटवर सिंह जी, इतिहास के पन्ने कम से कम बाद में गवाही देंगे, आज आप यहां पर मौजूद हैं और मैं इस बात का जिक्र यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि ईरान ने आपको बुलाया था और आपने कहा था कि हम भी विश्व शांति में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रफसंजानी ने कहा, ''राजीव जी, अगर आप विश्व शांति के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं, तो ईरान एक मुल्क के रूप में आपका सहयोग लेना चाहता है। भारत को तो छोड़ दीजिए, ईरान कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दोस्त देश रहा है। दुनिया के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब सरकारी प्रतिनिधिमंडल बैठा हो, उस समय एक गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल को भी निमंत्रण दिया जाए और कहा जाए कि तुम हमारे दोस्त हो। इस प्रकार उसने जिस कांग्रेस पार्टी की इज्जत की थी, आज उसी पार्टी की सरकार ऐसा कर रही है। आज उसी पार्टी की सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ईरान पर अगर हमने मतदान कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया।

मैं अभी श्री कपिल सिब्बल जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ''मैंने वोट दे दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया''। कपिल सिब्बल जी, मैं इसे गुनाह तब न मानता अगर आपने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपना मतदान किया होता। इसे मैं गुनाह इसलिए मानता हूं, नटवर सिंह जी आप उन्हें जानते भी होंगे, सीनेट कमेटी के चेयरमैन, जो फॉरेन एफेयर्स का कारोबार देखते हैं टॉम लिंटॉस, इन टॉम लिंटॉस ने आपके बारे में क्या कहा है, आप ज़रा यह भी सुन लीजिए। जब आप स्वतंत्र भारत के विदेश मंत्री की हैसियत से अपने काम का निर्वाह कर रहे थे, तब आपके बारे में यह कहा गया कि उनकी बुद्धि मोटी है। उनकी बुद्धि मोटी है, भारत इस चीज़ को समझ ही नहीं रहा है और मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को फैसला करना होगा कि वह ईरान के साथ जाना चाहता है या अमरीका के साथ जाना चाहता है। भारत बीच में नहीं रह सकता है।

उपसभापति महोदय, यह सीनेट कमेटी में दिए गए भाषण का एक अंश है और इसे मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह बात ऐसे ही नहीं कह दी गई थी और इसीलिए हमें शक होता है। यह बात लगातार कही जा रही है, यह बात 8 सितम्बर को कही गई है, यह रिपोर्ट में लिखा हुआ है। यह बात 8 सितम्बर से पहले की घटना के बारे में कही गई है। जब आपका पहला वोट होता है और उस वोट में आप हमारे उस परम्परागत मित्र के खिलाफ वोट करते हैं, तब हमारे मन में शक क्यों नहीं होगा? हमें शक क्यों नहीं होगा जब यहां पर बैठकर वहां का राजदूत कहता हो कि भारत को तय करना है कि भारत किसके साथ जाएगा। भारत को फैसला करना है कि वह ईरान का दोस्त है या अमरीका का और अगर न्यूक्लियर डील करनी है तो भारत को अमरीका के साथ जाना होगा, यह शक तो इसीलिए पैदा होता है। हम यहां कोई यह कहने के लिए खड़े नहीं हुए हैं कि आपको देश के साथ प्रेम नहीं है और हम ही को देश से सबसे अधिक प्रेम है। हम तो सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप उन लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, जिस देश का विदेश मंत्री, जिस देश का राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्दर कहता हो कि अमरीका को यह पूरी तरह से जानकारी है कि ईराक के पास वेपेन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। यह बात संयुक्त राष्ट्र की महासभा में सेक्योरिटी काउन्सिल में कही गई और उस समय सारी दुनिया ने इस बात का विश्वास कर लिया था। और नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि एक जीता जागता देश आज शमशान बना हुआ है, वहां रोज लोग मारे जा रहे हैं, हजारों की संख्या में मौत हो चुकी हैं और पता नहीं वहां यह युद्ध कब तक चलता रहेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधान मंत्री जी, हमारा शक इसलिए है, हमारा डर इसलिए है कि आज दबाव में काम कर रहे हैं। हम कोई अनजाने में आप पर यह तोहमत नहीं लगा रहे हैं कि आप जो नीति चला रहे हैं उस नीति से हमारा कोई मतभेद इसलिए है कि आप प्रधान मंत्री हैं। मैं तो शुरू में अपने भाषण का जिक्र करते हुए पं० जवाहर लाल नेहरू को आज भी कहता हूं, 1927 में जो लोग अगेंस्ट इम्पीरियलिज्म का

दस्तावेज तैयार हुआ था, मंत्री कोई आए, चाहे जसवन्त सिंह जी आए हों या नटवर सिंह जी आए हों, थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ हो, बुनियादी बात विदेश नीति में नहीं बदली गई। पहली बार ऐसा हो रहा है। हम जब गरीब थे, 1947 में तो 92 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे, हम अमेरिका का गेहूं खा रहे थे, तब भी हमने हिम्मत करके अमेरिका के खिलाफ अपनी आवाज को बुलन्द करने का और संसद के अंदर अपनी बात को रखने का काम किया। आज कौन सी ऐसी बात आ गई और आप तर्क क्या दे रहे हैं कि राष्ट्रीय हित का। उपसभापति महोदय, हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय हित है? अगर आप सिर्फ राष्ट्रीय हित की बात ले लें, मैं विदेश मंत्री की हैसियत से जो थोड़ी बहुत मुझको जानकारी है, मैं गोपनीयता की शपथ में हूं, इसलिए मैं उन बातों को नहीं कह सकता। लेकिन मैं इस सदन के सामने एक बात पूछना चाहता हूं कि सेंट्रल एशिया में ईरान के अलावा कोई दूसरी एन्ट्री भी है आपकी? अफगानिस्तान में अगर चाबहार पोर्ट जो हम लोगों ने मिलकर बनाया, यह सरकार भी उस पर काम कर रही है। उसके अलावा क्या आप अफगानिस्तान जा सकते हैं? आप बात कर रहे हैं राष्ट्रीय हित की। आज राष्ट्रीय हित किसमें सबसे ज्यादा है? राष्ट्रीय हित उस देश के साथ है जिस देश ने संकट के किसी मौके पर हमारा साथ न दिया हो और एक देश जो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा हो। आपने गिना दिया वोट, कपिल सिब्बल साहब ने गिना दिया वोट कि इतने-इतने समय ईरान ने हमारे साथ वोट किया। लेकिन आपको मालूम है कि ईरान कितने समय हमारे साथ खड़ा भी रहा। इस बात को गिनाने की आपने कोशिश की? मैं चाहता हूं, इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई कि नटवर सिंह जी, आप इन बातों के गवाह हैं और आप यहां पर बैठे हुए हैं। हम यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय हित हमारा सध रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है और कहा गया इसलिए कि नाम-NAM बंट गया, पी-5 का वोट हो गया। नाम बंट गया तो यह किसकी गलती थी। नाम का नेतृत्व तो हमारे हाथों सौंपा गया था। दुनिया मानती है इसलिए मैं इस घटना का जिक्र कर रहा हूं कि 1991 में भी जब दुनिया यूनिपोलर हो रही थी तब भी ईरान के नेतृत्व में हम ही को बुलाया गया था। राजीव गांधी जी को बुलाया गया था, नटवर सिंह जी आप गए थे। तो नाम बंट गया इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। नाम से हमने क्या इनीसिएटिव लिया, कौन सा इनीसिएटिव नाम की तरफ से हुआ था जिससे नाम के लोगों ने कहा है कि हम भारत की सार्वभौमिकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। जो नेतृत्व हमारे ऊपर सौंपा गया था हम उस नेतृत्व को स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं हैं और दोष दे रहे हैं कि नाम बंट गया। अपनी गलती को स्वीकारने की, जब विदेश नीति पर चर्चा हो रही हो तो इन बातों को स्वीकारने की हिम्मत रखिए। अब पी-5 का इंटरेस्ट, आपने जो वोट दिया वियना में वह कहां गया? वह वहीं गया जहां पी-5 बैठती है। भारत जहां पंच था, यह कौन सा राष्ट्रीय हित का आपने अपना तय किया जो हमारी समझ में नहीं आता, जहां स्वयं पंच थे, जहां बंटवारे में आपकी एक भूमिका थी, उसमें आपने अपनी भूमिका को वोट डालकर कह दिया कि इसको पी-5 के पास ले जाओ। पी-5 ने वोट

किया तो वाजिब किया। चूंकि वह वहां वही फैसला करेंगे पी-5 के लोग बैठते हैं, वहां भारत बैठकर फैसला नहीं करेगा। इसलिए पी-5 और नाम का जो तर्क दिया कपिल सिब्बल साहब ने, यह बात हमारे जैसे छोटे लोगों की बुद्धि में नहीं आई। हम आपसे इतना ही गुजारिश करना चाहते हैं, हम आपसे यह नहीं कहना चाहते कि आप बुश साहब को दुत्कार कर भेज दीजिए, हम यह भी नहीं कहना चाहते कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति को यहां से कह दो कि हम ईरान के साथ ही खड़े रहेंगे, हम आपके साथ खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपनी भूमिका को समझिए। अगर आप चाहते तो ईरान से कह सकते थे कि ईरान, तुमको यह काम नहीं, यह काम करना चाहिए। क्या नटवर सिंह जी, आपको याद नहीं ईरान में बैठकर तेहरान में हम लोगों ने फैसला किया था कि राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से जाकर कहेंगे कि तुम इस युद्ध को शीत विराम करो। और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने किया था या नहीं किया था? भारत के कहने पर राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने 1991 में कहा कि हम एक तरफा सीजफायर करते हैं, हम एक तरफा युद्धविराम करते हैं, क्योंकि भारत ने हमसे कहा था। आपके दोस्त, आपके ऊपर जान लुटाने वाले लोग और उनको आप कहते हो कि हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, हम आपसे क्या कह सकते हैं। हम भारत के प्रधान मंत्री जी, उनके साथ भी अनुभव का इतना बड़ा तजुर्बा, उनके साथ भी इतना बड़ा 50 साल तक इस देश की सेवा का हिस्सा और जिम्मा सब कुछ है। लेकिन अगर वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पायें और आप कहते हो कि हम पर आरोप लगाया। जब सुषमा जी बोल रही थीं, थोड़ा-बहुत सीताराम येचुरी जी ने भी कहा ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश): आप उस समय उपमंत्री थे, आप ईरान में बैठे थे, मैं भी उस वक्त वहां था। आप अमेरिकी जहाजों को रि-फिलिंग का आर्डर दे रहे थे। ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: हां, दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल: और आज यहां भाषण दे रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: मैं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)... मैं उन लोगों में से नहीं हूं। ...(व्यवधान)... आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइये। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल: जब राजीव जी अपोज़ कर रहे थे। ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। आप बैठ जाइये। अब अगर अटल जी इस सदन में नहीं हैं, यह राजीव गांधी ने कहा था कि रि-फीलिंग करो, अगर हमसे सुनना चाहते हो, नटवर सिंह जी दिल पर हाथ रखकर इस बात को बोल दें। ...(व्यवधान)... जी, इन उनकी सरकार से ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणि: चेहरा पुराना है। ...(व्यवधान)...

SHRI BALBIR K. PUNJ: He is speaking very well. He is making a very important point. ...(*Interruptions*)...

श्री उपसभापति: आप कंटीन्यु करिये। ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: जी। ...(व्यवधान)... उपसभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था इस सदन में और इस सदन के माध्यम से इस देश के प्रधान मंत्री जी से जो कुछ ही समय में यहां आने वाले हैं। मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी, आप हम पर आरोप लगा सकते हो, हमारे वामपंथी मित्र लोग हमसे नाराज रहते हैं और हमसे हमेशा यह कहते हैं कि आप अमेरिका परस्त नीति चलाते रहे, लेकिन क्या मैं अपने वामपंथी साथियों से एक सवाल पूछ सकता हूं। आप ही का दबाव था, विपक्ष का ही दबाव सही, लेकिन क्या आप इस बात की शाबासी हमें नहीं दे सकते कि हमने इस देश की सर्वानुमति को स्वीकार किया। जब इराक के सवाल पर इस संसद में प्रस्ताव रखा गया, तो उस समय हम बहुमत में थे, हम चाहते तो आपका प्रस्ताव नहीं मानते, लेकिन हमें लगा कि पूरा देश एक है, जो लोग राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, उन्हें मैं जवाब देना चाहता हूं कि जो आप हम पर आरोप लगा रहे थे कि हम अमेरिका परस्त विदेश नीति चला रहे हैं, लेकिन हम वही लोग हैं, जो आपने कहा कि इराक के युद्ध को कंडेम किया जाये, अमेरिका जो कुछ कर रहा है वह गलत कर रहा है, तो इसी भारत की संसद में हमने उस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए अपने को न्यौछावर किया। उसकी निंदा की। मैं वही कह रहा हूं कि आज सरकार जिसके भरोसे चल रही है, ...(व्यवधान)... सरकार जिसके भरोसे चल रही है, आप कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय सहमति की सरकार बनाना चाहते हैं, हम तो विपक्ष में हैं, हमारी बात को स्वीकार मत करो। लेकिन आपके मित्र समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, आपके मित्र वामपंथी दल बैठे हुए हैं, पूरा देश आज इस सवाल पर बंटा हुआ है। ...(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दास मुंशी): उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि इराक के हमले के समय, उस समय दोनों सदनों में यह चर्चा हुई थी, एक दिन नहीं लगातार दस दिन की इसकी निंदा सरकार की तरफ से की जाये, लेकिन सरकार खामोश रही और हाउस का डेडलॉक हटाने के लिए स्पीकर साहब को और चेयरमैन साहब को सभी को बुलाकर के एक निंदा प्रस्ताव चेयर की तरफ से लाया गया, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह: सरकार ने स्वीकार किया, तभी तो यह हुआ। हम तो उस समय बहुमत में थे। हम चाहते तो उस प्रस्ताव का विरोध कर देते। ...(**व्यवधान**)... प्रस्ताव हम ही लाये, प्रस्ताव हमने ही बनाया था। ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी (उत्तर प्रदेश): जब सदन की सहमति होती है तभी तो स्पीकर उसको रखते हैं। ...(**व्यवधान**)... It was not a part of the ...(*Interruptions*)...

श्री दिग्विजय सिंह: अब अगर उनको ज्ञान नहीं है, तो हम माफी चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति महोदय, मैं उस समय संसदीय कार्य मंत्री थी और मैं उसकी साक्षी हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: 1991 में भी ...(**व्यवधान**)... सदन में ...(**व्यवधान**)... हमेशा जब भी कोई सदन की तरफ से प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप बोलिये। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: जब भी कोई प्रस्ताव सदन की तरफ से स्वीकार किया जाता है, तो स्पीकर और चेयरमैन रखते हैं, वह सरकार की तरफ से नहीं आता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: श्री दिग्विजय सिंह जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री दिग्विजय सिंह: संसद का प्रस्ताव हमेशा स्पीकर की तरफ से आता है। ...(**व्यवधान**)... हमेशा चेयरमैन की तरफ से आता है। इसलिए आप अपने ज्ञान को थोड़ा ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: श्री दिग्विजय सिंह जी, आप जरा कन्क्लूड कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त ही कर दूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अभी इतना ही सरकार से कह रहा था कि अगर सचमुच में सरकार चाहती है, आज भी यह देश की ताकत है, इस देश में प्रधान मंत्री आयेंगे और चले जायेंगे, इस देश में 15 प्रधान मंत्री हो चुके हैं, प्रधान मंत्रियों की कुर्सी खाली नहीं रहती है, कोई न कोई इसको भर देता है, कोई न कोई सरकार इस देश में आयेगी। लेकिन यह देश रहेगा, इस देश के बुनियादी सिद्धांत रहेंगे और वह बुनियादी सिद्धांत हमें बार-बार कहता है, उपसभापति महोदय, हम किसी भी कीमत पर उन कामों को करने के लिए तैयार न हों, जिन कामों के लिए हमें आज बाध्य किया जा रहा है। इसीलिए में फिर कांग्रेस के लोगों से अपील के तौर पर कहना चाहता हूं, प्रधान मंत्री से अपील के तौर पर कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी, आप दुनिया में जो चाहें सो कर लें, आप जिन बातों को कह रहे हैं उन पर दुनिया यकीन करने के लिए तैयार नहीं है उस बात पर। आप कह रहे हो कि बगल में पाकिस्तान ताकतवर हो जायेगा। पाकिस्तान के पास तो पहले से ही न्यूक्लीयर बम मौजूद है। कौन-सी ताकत ईरान हो जायेगा? अभी कपिल सिब्बल साहब कह रहे थे कि बेसमेंट बम नहीं चाहिए, कौन-सी ताकत रह जायेगी पाकिस्तान की अगर ईरान के पास बम आ ही गया तो हम यह पूछना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल: आप यही चाहते हैं?

श्री दिग्विजय सिंह: नहीं, हम नहीं चाहते हैं। ...(व्यवधान)... आप यह सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान की ताकत कैसे कम हो जाती है और कैसे बढ़ जाती है, यह हम पूछना चाहते हैं? ...(व्यवधान)...

श्री राशिद अल्वी (आन्ध्र प्रदेश): दिग्विजय जी ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आप बैठ जाएं। ...(व्यवधान)...

श्री राशिद अल्वी: एक मिनट सर, अटल जी का और ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: देखिए, अब बहस के लिए वक्त नहीं है।

श्री राशिद अल्वी: वाजपेयी जी का और क्लिंटन का ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: आप बोल लेने दीजिए न। ...(व्यवधान)... प्रधान मंत्री बोलेंगे न आपकी तरफ से। सब बातों का जवाब दे देंगे।

श्री राशिद अल्वी: क्लिंटन का और वाजपेयी जी का एक ऐग्रीमेंट है, इसके अंदर पहली लाइन है कि India and the United States share the commitment of reducing, and ultimately eliminating, nuclear weapons. कैसे ईरान का साथ देंगे आप? ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: ठीक बात है। कौन न्यूक्लियर वैपन बना रहा है? मैं तो यही आपसे ...(व्यवधान)... राशिद साहब, मैं यही बात तो कह रहा हूं ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: निरस्त्रीकरण चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री दिग्विजय सिंह: राशिद साहब, मैं वही बात तो कहना चाहता हूं कि न्यूक्लियर वैपन के खिलाफ हम और आप हैं, लेकिन आप उस राष्ट्र की बात को स्वीकार करने को तैयार हैं जिसने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे इराक को शमशान के रूप में बदल दिया?

श्री उपसभापति: आप कनक्लूड कीजिए। दिग्विजय सिंह जी, प्लीज़ कनक्लूड कीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह: उपसभापति महोदय, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं ...(व्यवधान)... मुझे खुशी है राशिद साहब, आपने उस बात को छेड़ दिया जिसको मैं कहना नहीं चाहता था। मैं यही बात कहना चाह रहा हूं। ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वैपन नहीं है। दुनिया में किसी जगह यह सबूत नहीं मिला है कि कोई न्यूक्लियर वैपन ईरान के पास है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं और आप उस देश पर यकीन कर रहे हैं, जिस देश ने एक पूरे मुल्क को शमशान के रूप में परिवर्तित कर दिया है। हम इसलिए सचेत होने की बात कह रहे हैं। याद रखिए, प्रधानमंत्री जी,

आप कल रहें या न रहें, हम रहें या न रहें, जो आज अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है, मैं थोड़ा अगर दूर देख रहा हूं तो दस साल के बाद वही हालत हमारे साथ भी होने वाली है, इस बात को इन्कार करने की कोशिश मत कीजिएगा। (समय की घंटी) सरकार में कोई भी आ सकते हैं, लेकिन जो देश हमेशा अपनी दादागिरी, अपना दम्भ, अपना अहंकार दुनिया में स्थापित करना चाहेगा, वह भारत जैसे स्वतंत्र राष्ट्र को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में नहीं देख सकता है। यह नियति में है, साम्राज्यवादी नियति में यह बात होती है कि जिसका अपना अहंकार होता है, वह दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता और अगर यह बात सही है कि हम इतनी ही सरकार से अपील करना चाहेंगे, अभी भी मौका है और 6 तारीख को होने वाले वोटिंग के दिन - अब आप दो बार वोट कर चुके हैं - हम खिलाफ तो नहीं, लेकिन abstain करने के लिए आपसे अपील करेंगे, उस दिन आप abstain करके दुनिया में भारत की साख और इज्जत को बचा सकते हैं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Manoj Bhattacharya. You have three minutes.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Thank you very much, Deputy Chairman, Sir, It is very difficult to conclude within three minutes. So many points have been raised in this House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All points have been made. You have to just participate. Please, participate and give some important inputs.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, this is something very peculiar. Every time, the axe falls on me. It is very unfortunate, Sir. It is very unfortunate.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is to be done? Whether it is you or somebody else, it has to fall on somebody!

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I shall try to be as brief as possible.

Sir, I would like to express my deepest sense of anguish on the role that has been adopted by India in the voting pattern of International Atomic Energy Agency, whether it be on 24th September, or in the month of February, or the position contemplated to be taken on 6th March.

Sir, I personally feel, and feel very strongly, that the situation is quite fluid in the Middle-East. But that does not mean that we should have a fluid foreign policy. We cannot have a stable situation in the Middle-East, but we can have a stable foreign policy. That is the sign of

a strong nation. A strong nation must have a strong, stable and independent foreign policy. That is one thing.

Secondly, we are tending to believe the myths that have been propagated by the imperialist interests. I must say here that I am an unrepentant follower of the ethos and traditions of India's Independence Movement. That has taught me to oppose imperialism and colonialism. If I start narrating our experience and the history of American imperialism, right from the time of Roosevelt to George Bush, it would take hours. I know how even Roosevelt, though he was otherwise an admired person, told about Papa-doc of Haiti, "I accept that he is a son of a bitch, but is our son of bitch." That is the psyche of American imperialism. When

5.00 P.M.

Saddam was toeing the line of American imperialism, Saddam was a man Friday of American imperialism. When Saddam wanted to behave independent or when he tried to assert himself, he became the arch foe of American imperialism. Sir, that is the type of American imperialism. But I am sorry that my friends in the Government are trying to propagate or accept the myths being created by American imperialism. What is the proof? There is no proof that Iran is processing nuclear bomb. Sir, I am against the nuclear proliferation, not only the nuclear proliferation for that matter, but I am also against the peaceful use of the nuclear power. I am also against that. I am against the division of atom. Virtually, I am against the division of atom because that has created the catastrophe in this world 77Hiroshima and Nagasaki in 1945 on 6th and 9th of August. No terrorist organisation bombed Hiroshima; no terrorist organisation bombed Nagasaki. Lakhs of people were not killed by terrorist organisation. They were killed by American imperialism. Harry Truman was not Osama Bin Laden. Harry Truman was the President of the most admired democracy of the world, that is, America, the United States of America. He bombed Hiroshima and Nagasaki after the conclusion of the Second World War where millions of people were killed. So, Sir, I personally agree that we should be extremely careful. And whose national interest, Sir? My friends, Sitaram Yechury, he has spoken at length about the enlightened national interest — a new coinage, a new word that is being used, a prefix being used. Whose interest? How are you dividing the nation? How have you lost your position in the comity of nations? Sir, I don't have time in my favour, but I would like to say that please

don't be guided by the threatening of American Senators. My friend and erudite colleague, Digvijay Singhji, has already referred Tom Lantos, perhaps the President of the American Senate. How has he threatened even on the 23rd night? It is right that the decision was taken in the mid-night. Threatening came from Tom Lantos. It is being told that the representative of India was advised to vote against. Sir, my whole submission to the Government is that we are supporting you on the basis of the National Common Minimum Programme. It is clearly mentioned in it that you are following an independent foreign policy. Even though I understand that the foreign policy is the true reflection of the domestic policy what you are pursuing. If you persue a retrograde domestic policy, you cannot pursue a progressive foreign policy. That is not possible. I do not believe in rhetoric. Now, this Government is tending to pursue a retrograde internal domestic policy - the policy of globalisation. The earlier Government was also implicated in this, and for this the people of this country discarded the earlier Government. The same set of policies of liberalisation, privatisation and globalisation at the behest of the American imperialism, at the behest of the developed countries, and at the behest of the imperialist countries you are trying to follow. So, I do not expect that while following this retrograde domestic policy, you will be able to follow the progressive or an independent foreign policy. But I shall appeal that once you are given the scope, please do abstain from voting. This is our well-thought suggestion to you. If you take it as a suggestion, if you take it as a submission, if you take it as an advice, we shall say, kindly do refrain from voting. Don't vote. Don't associate with the American imperialism. The American imperialism is the most hated institution in this world. If you want to vote against the emancipation of people, against the freedom of people, against the democracies of the world, then, therefore, I shall feel ashamed to be a person supporting the Government when the Government toes the line of American imperialism. With these few words, I conclude. Thank you.

DR. CHANDAN MITRA (Nominated): I thank you, very much Mr. Deputy Chairman for giving me time at the fag end when many of the points have been gone through. Sir, the first point that I would like to make is that I feel the entire debate, although of very high quality, has been a little unfortunate because we have oscillated between unenlightened fatalism on one side, and unenlightened America bashing

on the other. I think neither position really serves the interest of this country or the interest of our foreign policy. At one level, I find a certain fatalism which is determining the Government's policy. We heard the hon. Minister. Mr. Kapil Sibal said, hope that perhaps this matter will not come up to a vote because some deal is being worked out between Russia and Iran. And, so perhaps, the vote will not happen at all. So, I believe that we, as a nation, a major nation in the world, a claimant for a permanent seat in the U.N. Security Council, cannot take a position that we hope that the issue does not come up. We should have certain clarity of position, clarity of perspective and vote according to our convictions. So, let us not leave things to fate. This situation would not have arisen, I believe, had the Government taken views of all the parties into consideration, discussed the matter, and instead of what the Leader of the Opposition described as a midnight decision, had we had a proper consensus being evolved in the country. But, I think, it is very unfortunate indeed that the Government did not go through this process of consultation and as a result, it is in a sorry position today of being attacked by even its own allies apart from the Opposition. On the other hand, we find a situation where, I think, because of this lack of confidence building, we have an anti-American position being expounded by a large number of political parties and individuals. I don't think even that is in the larger national interest. As the Minister, Shri Kapil Sibal, talked about what is the most advantageous position to take for the country, he quoted Pandit Nehru for that. I think this is what should be guiding our national interest, should be guiding our action in respect to every foreign policy objective not just in this matter but others. Now, here, Sir, what should have been our national interest and how should we have gone about it? I have a few submissions here. First, India should have behaved like a big power that it aspires to be. It should not be taking decisions that appear to be smuggled in through the backdoor. Some days ago, an Ambassador of one of the Central Asian countries came to visit me and said that he was surprised by the India's ambivalence and India's equivocation on the question of Iran and the vote. He said, "I do not understand why India is not behaving like a big power that it is, not setting the agenda or not seeming to be following an independent policy." I think that is a very serious matter and I would urge the Government to keep this in mind because the matter is not over; after this, other issues are going to arise and it is important that how we are seen. If we are claimants of a great power status, I think, it is important

that how we project ourselves. This was an opportunity to take an independent foreign policy position and make our position clear on this. This was not done. Second, this was an opportunity for us, I would say a huge opportunity — does not matter which way we vote; that, I think, is secondary — for us to expose Pakistan's perfidy, and the way Pakistan has aided and abetted this entire nuclear programme as Shrimati Sushma Swaraj, in her inaugural speech, mentioned and detailed. Sir, now, this is internationally documented. I am reading from Guardian Report of January, 2006: "Mr. A.Q. Khan is known to have visited Sudan, at least, once between 1998 and 2002 and the suspicion is that he may have used the country as a warehouse for the high-tech engineering equipment he was selling to Libya, Iran and North Korea for the assembly of centrifuges for enriching uranium, the most common way of building a nuclear bomb." Sir, this was an opportunity for India, for our entire foreign policy establishment, to expose Pakistan's perfidy, to expose Pakistan's role in this. I saw it on television yesterday where a U.S. Congressman was saying, "We are opposed to the Indo-US nuclear deal because what we will tell Pakistan when Pakistan demands the same tomorrow." Now, when tomorrow situation comes, when Pakistan demands parity with India, when Pakistan demands the same, this background would help us enormously in creating or intensifying public opinion world wide against the Pakistan's perfidy and Pakistan's role in helping Iran build this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, conclude.

DR. CHANDAN MITRA: Sir, I am just concluding. Third, this was an opportunity for us to secure our energy needs, energy security to be ensured. This point has been touched upon, but I think, it is very important that we should have trodden a line without antagonising our age-old friends, on civilisational terms, on diplomatic and foreign policy terms, Iran and we have had differences, but these are civilisational linkages that are there. Iran also needs to sell its energy; we need energy. We should have been able to work out a deal the same way as Russia and China worked out a deal. Russia voted against Iran but this should be noted that Russia is supplying the Air-Defense system for Iran beginning April. Russia is providing that cover. So, every country has to look after its own enlightened national interest but, unfortunately, we did not do that. We have left it to fate and we have left it to anti-Americanism, and, I don't believe either of this has served India's policy well. I hope that in future when this situation comes, the whole country will be taken into

confidence, all political parties will be taken into confidence, and, a certain policy will be worked out which will be in the larger national interest of the country and it would not appear that midnight confabulations and midnight decisions are determining our foreign policy. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri R.S. Gavai. You have three minutes.

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Sir, I would just like to express my views before the House and I will take hardly two minutes. At the outset, Sir, I appreciate the statement made by the Prime Minister on 17th February, 2006. I sincerely feel that the statement made by the hon. Prime Minister is in keeping with the reality and is a quite balanced one. It is balanced in the sense that the Prime Minister also reaffirmed the traditional close and friendly relations with Iran. Indo-Iran relations and ties are of civilization in nature. He further mentioned that we entered to further strengthen these relations.

Sir, keeping in view the fast changing geo-political situation across the globe, a dynamic foreign policy is essential. Sir, in the international fora, we will have to be solely guided by the enlightened national interests. Many countries with whom we have friendly relations, they also follow the same logic of their own national interest. Sir, I would like to mention the words of Dr. Ambedkar which he uttered at the time of the Chinese Aggression. Earlier, we had good relations with China. It is a very exhaustive speech but as far as some salient features of this speech are concerned, he said, "There are no permanent enemies, there are no permanent friends. Self-interest is only the permanent and only the paramount." I think this quotation is quite in keeping with the statement of the Prime Minister.

But still the option is open to find out a diplomatic way out. It appears in the Press that Iran seems to have reconciled. The proposal is to let Iran enrich uranium for energy purpose on the Soviet territory. Sir, the hon. Prime Minister hopes and he talks of locating nuclear enrichment facilities in Russia.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude, Mr. Gavai.

SHRI R.S. GAVAI: I am concluding, Sir. Iran's needs would have a positive outcome. Hon'ble Prime Minister also further expressed his sincere hope and belief that the issue can still be resolved through discussion and dialogue. Thank you.

श्री मंगनी लाल मंडल: महोदय, मेरे पास कितना टाइम है। उपसभापति महोदय, दल की स्थिति के अनुसार मेरा नाम तो सातवें नम्बर पर था, लेकिन मैं अब अन्त में आ गया हूं, जब सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं।

उपसभापति महोदय, वाद-विवाद का स्तर बहुत ऊंचा रहा और सारे माननीय सदस्यों ने अच्छे विचार प्रकट किए। सुषमा जी का भाषण बहुत सारगर्भित होता है। आज भी उन्होंने सारगर्भित भाषण दिया। दिग्विजय जी का भी सारगर्भित था, लेकिन वे बहुत आक्रोश में थे।

(श्री सभापति पीठासीन हुए)

प्रधानमंत्री जी ने 17 फरवरी को जो बयान दिया, उसमें सारी स्थिति को स्पष्ट किया गया है, चर्चा की गई है। आईएईए में भारत के पास वोट देने की तीन स्थिति व विकल्प था - एक कि भारत प्रस्ताव के पक्ष में मत दे या नहीं दे। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। दूसरा भारत प्रस्ताव के विपक्ष में मत दे, जैसा क्यूबा और दूसरे देशों ने किया। वह अमेरिका के खिलाफ जाता, तो यह कुछ लोगों को अच्छा लगता कि अमेरिका के खिलाफ एक लॉबी बनी। भारत ने ऐसा नहीं किया। तीसरा भारत को तटस्थ रहना चाहिए, जैसा दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया आदि देशों ने किया। भारत ने तटस्थ रहना कबूल नहीं किया। कई माननीय सदस्यों ने, दिग्विजय जी ने पीएल 480 का उल्लेख किया। पीएल 480 के समय में दो ध्रुव थे - सोवियत संघ और अमेरिका। तब भारत की तटस्थ नीति का एक दूसरा महत्व था। आज हम एक शक्तिशाली देश हैं और सोवियत संघ नहीं है। भारत की जो तटस्थ नीति है, उसको अपने इंटरेस्ट में एक प्रभावकारी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निभानी है। भारत ने यही फैसला किया कि भारत निर्णय लेता है अपने इंटरेस्ट में, जो हमारा राष्ट्रीय हित है, उस राष्ट्रीय हित में हम विदेश नीति का परिपालन करेंगे। भारत ने यही किया। महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है या नहीं बना रहा है, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि ईरान का जो दायित्व है, उसमें जवाबदेही नहीं है। एक जवाबदेह राष्ट्र के रूप में आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है।

माननीय नेता, विरोधी दल ने टू डिकेड की बात की। कई अखबारों में यह खबर आई है कि 18 वर्षों से यह चल रहा था। लेकिन यह मामला प्रकाश में कब आया? यह प्रकाश में तब आया, जब कुछ लोग ईरान से भाग कर बाहर गए और यह कहा कि पाकिस्तान के सहयोग से, गुपचुप तरीके से, गुप्त तरीके से ईरान में नाभिकीय परमाणु के संवर्द्धन की कार्रवाई चल रही है। तभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह खलबली मची और जब खलबली मची, तो आईएईए ने उनसे क्लैरिफिकेशन पूछा। इसका ईरान ने कभी ठीक से जवाब नहीं दिया। जितने बिन्दुओं पर भी सवाल पूछे गये उसमें एक बिन्दु रह गया, सेंट्रिफ्यूजेज के बारे में, जिसकी चर्चा की गई है। आज तक ईरान से इसे स्पष्ट रूप से नहीं रखा। मान्यवर प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसमें

इसका उल्लेख किया है। महोदय, मैं उसे दोहराना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ''अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक की उत्तरोत्तर रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि यद्यपि ईरान के सहयोग से अनेक प्रश्नों का स्पष्टीकरण मिल गया है, फिर भी महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़े हुए कई प्रश्नों का अभी समाधान नहीं हो पाया है, जो ईरान को करना है।'' फिर आगे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसमें तीसरे देशों से, जिसकी चर्चा कपिल सिब्बल जी ने की है, माननीय कपिल सिब्बल साहब ने बहुत स्पष्ट स्थिति रखी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है एस्थेटिक सेंट्रिफ्यूजेज का इस्तेमाल और मेटैलिक हेमिस्फेयर के निर्माण से सम्बन्धित डिजाइन शामिल है। यह डिजाइन कौन बना रहा है? यह ईरान बना रहा है। महोदय, इतना ही नहीं, ईरान ने कहा कि कुछ देशों को हम दुनिया से मिटा देंगे। कोई जवाबदेह राष्ट्र ऐसा नहीं कह सकता है। जब आईएईए ने तेहरान के बगल में, जिसकी चर्चा माननीय श्री सिब्बल साहब ने की है, इस्फाहन और दूसरी जगह नतांजा, इन दोनों को आईएईए ने सील कर दिया और कहा कि परमाणु संवर्द्धन की आगे की कार्रवाई ईरान में तब तक नहीं होगी, जब तक आईएईए का समाधान नहीं हो जाता है कि गुप्त तरीके से ईरान कोई नाभिकीय परमाणु के संवर्द्धन का काम चला रहा है। ईरान ने क्या किया कि इस्फाहन का कार्य पुनः प्रारम्भ किया, उसका सील तोड़ दिया। आईएईए ने नतांजा में जो सील किया था, उसे भी ईरान ने गैर कानूनी तरीके से उस सील को तोड़ दिया। इस तरह ईरान उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य नहीं कर रहा है।

अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी दिग्विजय जी ने कहा ईरान तो हमारा दोस्त रहा है। हम इस से इंकार नहीं कर सकते, लेकिन पहली बार 1974 में जब मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया था तो ईरान ने हमारी खिलाफत की थी। यह बात सही है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे खिलाफ गया था। फिर जब आप की सरकार थी व माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे और 1998 में जब भारत ने पुनः परीक्षण किया तब भी इंडिया पर सैंक्शन लगाने के लिए ईरान ने हमारे खिलाफ वोट दिया था। लेकिन अमेरिका के खिलाफ लॉबी बनाने में हम अपनी शक्ति को बर्बाद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। हम तटस्थ रहें तो हमारी भूमिका भी तटस्थ होनी चाहिए, लेकिन निर्णायक और प्रभावकारी होनी चाहिए। ईरान ने काश्मीर के सवाल पर कभी हमारा साथ नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार आयोग में भी हमारे खिलाफ वोट दिया। इसीलिए सारी बातों को लेकर राष्ट्र हित में जो भी समझौता हो व भारत ने इस बारे में जो भी काम किया है और आगे जो भी काम करेगा मैं उस का समर्थन करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

MR. CHAIRMAN: Now, the hon. Prime Minister will make a statement on Civil Nuclear Energy Cooperation with the United States.